04 - ज्ञान का भ्रम पैदा करते स्कूली पाठ्यक्रम की दिशा

05 - क्या बच्चों की सुरक्षा सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी?

A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 25 जून, 2026

06 - पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा : दीपक वोहरा

07 - एडीबी विशेषज्ञों ने बुधनी टॉय विलेज परियोजना का किया...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 293, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

युद्धविराम से आगे : क्या विश्व अहिंसा की ओर बढ़ेगा?

ललित गर्ग

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हाल ही में हुआ युद्धविराम ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम एशिया युद्ध की लपटों में घिरकर वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। कई सप्ताह तक चले संघर्ष ने क्षेत्र को ऐसे ज्वालामुखी में बदल दिया था, जिसकी प्रत्येक विस्फोटक घटना विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोर रही थी। तेल बाजारों में भारी उथल-पुथल थी, निवेशकों में घबराहट बढ़ रही थी और वैश्विक मंदी की आशंकाएं गहराने लगी थीं। ऐसे में युद्धविराम ने विश्व को तत्काल राहत तो दी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह समझौता स्थायी शांति की नींव बनेगा या केवल अगले युद्ध से पहले का एक अस्थायी विराम सिद्ध होगा? इतिहास साक्षी है कि युद्धविराम और शांति समझौते तभी टिकाऊ सिद्ध होते हैं, जब उनके पीछे केवल सामरिक विवशता नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारस्परिक विश्वास और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता भी हो। अन्यथा वे केवल संघर्षों के बीच का अंतराल बनकर रह जाते हैं। पश्चिम एशिया का इतिहास ऐसे असंख्य समझौतों का गवाह है, जो कागजों पर तो बने, लेकिन जमीन पर टिक नहीं सके।

इस युद्ध के परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो सबसे बड़ा लाभार्थी ईरान दिखाई देता है। अमेरिका और इजरायल के सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बावजूद तेहरान न केवल अपने राजनीतिक ढांचे को बचाने में सफल रहा, बल्कि उसने अपने विरोधियों को वार्ता की मेज पर आने के लिए भी बाध्य किया। ईरान अब अपने नागरिकों के समक्ष यह दावा कर सकता है कि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। ईरानी नेतृत्व इसे प्रतिरोध की जीत के रूप में प्रस्तुत करेगा। दूसरी ओर इस संघर्ष ने अमेरिका की अजेयता की छवि को भी चुनौती दी है। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के बाद यह एक और अवसर है, जिसने यह स्पष्ट किया कि केवल सैन्य शक्ति राजनीतिक परिणाम सुनिश्चित नहीं कर सकती। वाशिंगटन ने दबाव बनाया, अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः उसे वार्ता और समझौते का रास्ता अपनाना पड़ा। इससे यह संदेश गया है कि इक्कीसवीं सदी की दुनिया अब केवल शक्ति संतुलन से नहीं, बल्कि संवाद, कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग से संचालित होगी।

इजरायल के लिए यह स्थिति राजनीतिक रूप से असहज है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को अपने देश के अस्तित्व के लिए खतरा बताते रहे हैं। इजरायल को आशा थी कि युद्ध के माध्यम से ईरान की सामरिक क्षमता को निर्णायक रूप से कमजोर किया जाएगा। किंतु युद्धविराम के बाद ईरान स्वयं को विजेता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इससे इजरायल के भीतर यह बहस और तीव्र हो सकती है कि क्या क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं की तुलना में महाशक्तियों ने अपने सामरिक हितों को अधिक महत्व दिया। भारत के लिए यह समझौता विशेष महत्व रखता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भर है। युद्ध की स्थिति में तेल आपूर्ति बाधित होने, समुद्री व्यापार मार्गों पर संकट उत्पन्न होने और कीमतों में वृद्धि की आशंका ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। युद्धविराम से तेल कीमतों पर दबाव कम होगा, महंगाई नियंत्रित रहेगी और खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी घटेंगी। लेकिन भारत का महत्व केवल एक उपभोक्ता राष्ट्र के रूप में नहीं है, वह आज वैश्विक शांति के एक नैतिक प्रवकता के रूप में भी उभर रहा है।

दरअसल, यह युद्ध एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है- क्या मानव सभ्यता युद्धों के सहारे अपने भविष्य का निर्माण कर सकती है? आज महाशक्तियों ने ऐसी विनाशकारी सैन्य क्षमता अर्जित कर ली है कि किसी भी देश की एक छोटी-सी भूल संपूर्ण मानवता को विनाश की ओर धकेल सकती है। परमाणु हथियारों, जैविक अस्त्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणालियों के युग में युद्ध अब केवल सीमाओं का प्रश्न नहीं रह गया है, वह समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। यही कारण है कि आज दुनिया को शक्ति की नहीं, शांति की राजनीति की आवश्यकता है। हिंसा, युद्ध, आतंकवाद और शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा ने मानवता को भय, अविश्वास और असुरक्षा के गर्त में धकेल दिया है। यदि विश्व को बचाना है, तो उसे निःशस्त्रीकरण, अहिंसा, सह-अस्तित्व और संवाद की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा।

इस संदर्भ में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत पर आधारित रही है, जो सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है। यही कारण है कि भारत ने सदैव युद्ध के स्थान पर संवाद और टकराव के स्थान पर सहमति का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व के अनेक मंचों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि 'यह युग युद्ध का नहीं है।' भारत की विदेश नीति आज एक नए स्वरूप में सामने आ रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष हो अथवा पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट-भारत ने किसी पक्ष विशेष का अंध समर्थन करने के बजाय संतुलन, संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की नीति अपनाई है। यही संतुलित दृष्टिकोण भविष्य में भारत को वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर कर सकता है। लेकिन केवल सरकारें ही शांति स्थापित नहीं कर सकतीं। शांति का आधार समाजों, संस्कृतियों और मनुष्यों के भीतर निर्मित होता है। जब तक राष्ट्रवाद आक्रामकता का रूप लेता रहेगा, जब तक हथियार उद्योग युद्धों को लाभ का साधन बनाकर चलता रहेगा और जब तक राजनीतिक नेतृत्व युद्ध को लोकप्रियता अर्जित करने के उपकरण के रूप में उपयोग करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति का सपना अधूरा रहेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व समुदाय कुछ ठोस कदम उठाए-परमाणु एवं सामरिक हथियारों की होड़ को नियंत्रित किया जाए, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए स्थायी संवाद तंत्र विकसित किए जाएं और शिक्षा प्रणालियों में शांति एवं अहिंसा के मूल्यों को शामिल किया जाए। साथ ही युद्ध अर्थव्यवस्था के स्थान पर मानव कल्याण आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता दी जाए। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हुआ युद्धविराम निश्चय ही राहत का क्षण है, किंतु इसे स्थायी शांति में परिवर्तित करना अभी शेष है। यदि विश्व समुदाय इस अवसर को आत्ममंथन का क्षण मानकर अहिंसा, संवाद और सह-अस्तित्व की नई वैश्विक संस्कृति विकसित करता है, तो यह युद्धविराम मानव इतिहास के एक नए अध्याय का प्रारंभ भी बन सकता है।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

ब्रिक्स की बैठक से विश्व को भारत का बड़ा संदेश

आतंकवाद और ग्लोबल साउथ पर मोदी ने खींच दी बड़ी लकीर

ब्रिक्स देशों के एनएसए से मुलाकात में भारत का सीधा संदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्रिक्स देशों को हर तरह से तैयार रहने को आगाह किया है। ब्रिक्स की अध्यक्षता अभी भारत के पास है, इस जिम्मेदारी के तहत इसने सदस्य देशों को हर उस मुद्दे को लेकर एकजुट रहने का आह्वान किया है, जो संकट भी बन सकता है और साथ मिलकर जिसका आसानी से समाधान भी निकला जा सकता है। भारत का यह नजरिया पहले ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आपसी बैठक में एनएसए अजीत डोभाल के माध्यम से जाहिर हुआ और फिर जब तमाम सदस्य देशों के एनएसए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी बड़ी स्पष्टता के साथ भारतीय दृष्टिकोण उनके सामने रख दिया।

ग्लोबल साउथ और आतंकवाद पर फोकस

पीएम मोदी ने मंगलवार को ब्रिक्स देशों के एनएसए से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत के द्वारा ब्रिक्स की अगुवाई करने से ग्लोबल साउथ को लेकर इसकी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एनएसए की बैठक की अजीत डोभाल ने की अगुवाई

ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक की अगुवाई भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। उन्होंने सदस्य देशों से कहा,हम यहां अलग-अलग महाद्वीप से आए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से हैं और यह ऐसा समूह है, जहां हमलोगों के पास विविध तरह का अनुभव है। अजीत डोभाल ने अपने समकक्षों से कहा कि ब्रिक्स सदस्यों को तय करना है कि वे उभरती चुनौतियों का मिलजुल कर कैसे सामना कर सकते हैं। डोभाल ने इस बात से आगाह किया कि सुरक्षा के आधुनिक खतरे तेजी से सीमाएं पार कर रहे हैं और रक्षा के परंपरागत तकनीक और कूटनीतिक फ्रेमवर्क को नाकाम करने लगे हैं।

रानी दुर्गावती के नाम पर नवीन संस्थान का जबलपुर में जल्द होगा लोकार्पण

अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और साहस की मिसाल थीं वीरांगना रानी दुर्गावती : मुख्यमंत्री

भोपाल/जबलपुर (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रानी दुर्गावती, अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और साहस की प्रतिमूर्ति थीं। नारी शक्ति का पराक्रम मां दुर्गावती के व्यक्तित्व में नजर आता है। मुगलों को युद्धों में धूल चटाने वाली ऐसी वीरांगना रानी दुर्गावती का आज 463वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती ने गौंडवाना साम्राज्य में 52 गढ़ों पर शासन किया। पति की असमय मृत्यु के बाद 5 साल के बेटे को सिंहासन पर बैठाया और 15 साल तक जनता की सेवा के लिए और क्षेत्र की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। मध्यप्रदेश की धरती पर लगभग 500 वर्ष पूर्व रानी दुर्गावती का जन्म हुआ, लेकिन आज पूरा देश और प्रदेश उन्हें आदर के साथ स्मरण करता है। हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश सरकार के गठन के बाद मंत्रि-परिषद की पहली बैठक जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित कर आयोजित की गई थी। इसके बाद दूसरी कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती के गौंडवाना साम्राज्य की राजधानी संग्रामपुर में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उनकी समाधि स्थल नर्रई नाला जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती को समर्पित नवीन संस्थान जबलपुर में 100 करोड़ रूपए की लागत से मदन महल के पास तैयार हो रहा है, जिसका लोकार्पण बहुत जल्द किया जाएगा।

समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन किये अर्पित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम की शुरूआत में ग्राम नर्रई नाला स्थित वीरांगना महारानी रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही गौंड समाज के आराध्य देवता बड़ा देव का पूजन-अर्चन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

किसानों के कल्याण के लिए ठोस निर्णय ले रही है सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित है और पूरा वर्ष किसानों को समर्पित करते हुए ठोस निर्णय ले रही है। अब किसान बंधुओं के लिए शून्य ब्याज दर पर 31 मार्च तक कर्ज चुकाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। किसान जिस तारीख को लोन लेंगे, तब से एक वर्ष की समयावधि में कर्ज चुकाया जा सकेगा। राज्य सरकार 880 करोड़ रुपए का भुगतान वित्तीय संस्थाओं को करेगी। राज्य सरकार पर्यटन, उद्योगों और अधोसंरचना विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शासकीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर सरकार किसानों को अब चार गुना मुआवजा देगी। प्रदेश में संचालित रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना से कोदो-कुटकी पैदा करने वाले किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश की लाड़ली बहनों को हर माह जारी हो रहे 1500 रुपए से उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। रानी दुर्गावती द्वारा किसानों के कल्याण के लिये चलाये गये कार्यक्रमों से प्रेरित होकर प्रदेश सरकार भी निरंतर कृषक हित में कार्य कर रही है। हमारी सरकार के पास किसान कल्याण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं है।

सुप्रभात

कोशिश के बावजूद ये
इल्ज़ाम रह गया
हर काम में हमेशा
कोई काम रह गया
छोटी थी उम्र और .
फसाना तवील था
आग़ाज ही लिखा गया
अंजाम रह गया
उठ उठ के मस्जिदों से
नमाज़ी चले गए
दहशत-गरों के हाथ में
इस्लाम रह गया
उस का क़ुसूर ये था
बहुत सोचता था वो
वो कामयाब हो के भी
नाकाम रह गया
अब क्या बताएँ कौन था
क्या था वो एक शख्स
गिनती के चार हर्फ़ों का
जो नाम रह गया।

- निदा फ़ाज़ली

कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहा, चार की मौत

● 50-55 लोगों के दबे होने की आशंका , 4 का रेस्क्यू-सेना भी बचाव में जुटी

कोलकाता (एजेंसी)। दक्षिण कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास बुधवार दोपहर 1.30 बजे निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक गिर गया। घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से 55 लोगों के दबे होने की आशंका है। अधिकारियों के मुताबिक 20 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका था स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के वक्त गोदाम में कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था। पुलिस के मुताबिक, रेस्क्यू में कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और सेना भी जुटी है। मलबे और लोहे की रॉड को हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई है। गैस कटर से लोहे की छड़ों को काटा जा रहा है। मलबे में दबे मजदूरों-कर्मचारियों की चीखें भी सुनाई दे रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू के प्रयास जारी हैं। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया बुधवार दोपहर के समय तारातला इलाके में ब्रेस ब्रिज के पास ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर स्थित एक निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक गिर गया।

रोहतांग की पहाड़ियों से ब्यास तक आएगा चिनाब का पानी

पंजाब-हरियाणा और हिमाचल को फायदा, टेक्निकल सर्वे पूरा

शिमला (एजेंसी)। चिनाब-ब्यास लिंक सुरंग परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना को भू-वैज्ञानिकों के गहन तकनीकी सर्वेक्षण से और मजबूती मिली है। भू विशेषज्ञों ने कोकसर और रोहतांग क्षेत्र की चट्टानों की टेस्टिंग की है। टेस्टिंग के बाद रिजल्ट आया है कि यहां की चट्टानें प्राकृतिक रूप से बहुत ठोस और मजबूत हैं। कोकसर और रोहतांग की घाटी ऊबड़-खाबड़ और यू शेप की है। इसकी चोटियां 3095 मीटर से लेकर 6517 मीटर के बीच फैली हैं। इलाके की पहाड़ियों की जो चट्टानें हैं वे रोहतांग नीस सम्मिश्रण, क्वार्टजो-फेल्डस्पैथिक नीस और बायोटाइट नीस चट्टानें हैं। ये चट्टानें बहुत मजबूत हैं। ये चट्टानें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि सुरंग और बांध निर्माण के दौरान लैंडस्लाइड की आशंका न के बराबर है।

चट्टानों के बीच से निकलेगा चंद्रा नदी का पानी

चंद्रा नदी के पानी को इन चट्टानों के बीच से निकालते हुए ब्यास नदी में में मिलाया जाएगा। चिनाब नदी पर बन रही इस परियोजना से न सिर्फ पानी का रुख भारत की ओर मुड़ेगा, बल्कि बड़े स्तर पर यहां बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। इससे पानी और बिजली दोनों की ही किल्लत खत्म होगी। गर्मी के सीजन में उत्तर भारत में पानी की कमी होती है। इस परियोजना के एक बार पूरा होने के बाद यह कमी खत्म हो जाएगी। चिनाब नदी के पानी को सुरंग कि जरिए ब्यास से होते हुए भाखड़ा बांध में लाकर मिला दिया जाएगा। चंद्रा, चिनाब नदी की सहायक है। इसे कंट्रोल करने के लिए 19 मीटर ऊंचे और 96.05 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने 2,620 करोड़ रुपये की प्रस्तावित चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना को राष्ट्रीय हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत के जल संसाधनों का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने नागरिकों और राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।

रामंदिर चोरी कांड

एसआईटी ने चंपत राय समेत 17 को आरोपी माना

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में स्पेशल इन्वेस्टीशन टीम यानी एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना है। इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से इस बात की जानकारी पता चली है। वहीं, एसआईटी आज फिर जांच के लिए अयोध्या पहुंच सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसआईटी टीम को दानपात्रों की चाबियां रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास मिलीं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 25 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

'छात्रों की गूंज' को दहशतगर्द बता रहे केन्द्रीय मंत्री प्रधान

- शिक्षा मंत्री पर भड़के कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा

है। उन्होंने कहा है कि 90 पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों छात्रों का भविष्य बरबाद हुआ है, 20 बच्चों ने नीट यूजी लीक की वजह से अपनी जान ले ली, परिवार तबाह हो गए। मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर चिपककर इंटरव्यू देते हुए छात्रों की गूंज को दहशतगर्द बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश ये भूला नहीं है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भरी संसद में अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक संज्ञा दी थी, जो इस सरकार से सवाल पूछता है, उसको देशद्रोही बोलते हैं।

जिन शिक्षकों पर भरोसा था उन्होंने धोखा दिया

- नीट यूजी विवाद पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, राहुल पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में बीते कई दिनों से विवादों में चल रहे नीट यूजी के मामले में अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों पर परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही इसके साथ धोखा किया और परीक्षा की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। रविवार को दोबारा हुई नीट परीक्षा के

बिना किसी गड़बड़ी के पूरे होने के बाद, शिक्षा मंत्री ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शिक्षकों को बहुत संवेदनशील जिम्मेदारियां सौंपी थीं, लेकिन कुछ लोग इस भरोसे को बनाए रखने में नाकाम रहे। उन्होंने 3 मई को हुई पहली परीक्षा में कुछ लोगों द्वारा किए गए विश्वासघात पर दुख जताया, जिसके कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। इसके साथ ही प्रधान ने विपक्ष की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों का जवाब भी देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा।

सीधी में सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था

दूल्हे जींस तो दुल्हनें सलवार-सूट में दिखीं, 43 में से 20 जोड़ों को नहीं मिले कपड़े

सीधी (नप्र)। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत बुधवार को सिद्धिविनायक मैरिज गार्डन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में लापरवाही सामने आई। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आयोजित इस सरकारी कार्यक्रम में कई जोड़ों को तय वेशभूषा (दूल्हे के लिए कुर्ता-पायजामा और दुल्हन के लिए साड़ी) तक नहीं दी गई। इसके चलते कई दूल्हे जींस-टीशर्ट और दुल्हनें सलवार-सूट में ही शादी की रस्में निभाते नजर आए।

20 से ज्यादा जोड़ों को नहीं मिले कपड़े- समारोह में कुल 43 जोड़ों का विवाह होना था, लेकिन इनमें से 20 से अधिक जोड़ों को शासन की तरफ से मिलने वाले कपड़े और सामान नहीं दिए गए। मजबूरन कई जोड़ों ने अपने पैसों से कपड़े खरीदकर शादी की रस्में पूरी कीं। चौफाल निवासी दूल्हे सीताराम बैगा ने बताया कि उन्हें प्रशासन की तरफ से केवल एक पगड़ी दी गई, बाकी कोई सामान या कपड़ा नहीं मिला।

भीषण गर्मी में सिर्फ एक वाटर कूलर- समारोह स्थल पर आए मेहमानों और जोड़ों के लिए व्यवस्थाएं बेहद खराब रहीं। कड़कड़ाती गर्मी के बीच करीब 200 लोगों के लिए सिर्फ एक वाटर कूलर और नौ पंखे लगाए गए थे। इसके उलट, वहां मौजूद अधिकारियों और नेताओं के लिए अलग से दो वाटर कूलर की व्यवस्था थी। इसके अलावा 43 जोड़ों की शादी कराने के लिए सिर्फ दो पंडित बुलाए गए थे। सुबह 10 बजे से आए जोड़ों को दोपहर 2 बजे तक शादी शुरू होने का इंतजार करना पड़ा।

इस अव्यवस्था पर जनपद पंचायत सीईओ चंदूलाल पनिका ने कहा कि उनका काम सिर्फ आयोजन संभालना था और सभी जोड़ों को घर से ही तैयार होकर आना था, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है।

वो कान्हा का राजा था...

एमपी में 'कुत्तों के वायरस' से 9वें बाघ की मौत

20 दिन चला इलाज, विशेषज्ञ भी नहीं बचा सके

मंडला (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों को विचलित करने वाली खबर सामने आई है। कान्हा के मुक्की क्वारंटाइन सेंटर में उपचाराधीन एक और बाघ ने दम तोड़ दिया है। शुरुआती जांच में मृत बाघ के भीतर घातक केनाइन डिस्टेम्पर (बीमारी के लक्षण मिले हैं। चिंताजनक बात यह है कि पिछले महज तीन महीनों के भीतर कान्हा में इस बीमारी के संदिग्ध लक्षणों के चलते यह 9वें बाघ की मौत है। कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक, 4 जून 2026 को किसली बीट के सन्दूक खोल इलाके में हाथी गश्ती दल ने इस बाघ को अत्यंत अस्वस्थ और कमजोर स्थिति में देखा था।

विसरा सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तय प्रोटोकॉल के तहत मृत बाघ का पोस्टमार्ट्म कराया गया। पीएम रिपोर्ट के अनुसार, बाघ के सभी महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित पाए गए हैं। मौत के सटीक कारणों और केनाइन डिस्टेम्पर की आधिकारिक पुष्टि के लिए विसरा (अंगों के नमूने) सुरक्षित कर फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। वरिष्ठ वन अधिकारियों और नामित सदस्यों की मौजूदगी में प्रोटोकॉल के तहत बाघ के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी !

ईरानी राष्ट्रपति ने कर दिया 'खेला', न्यौता देकर फंसाया

तेहरान (एजेंसी)। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। अली खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के शुरुआती हमले में मारे गए थे। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने खामेनेई के मौत पर कोई शोक संदेश नहीं जारी किया था। हालांकि, बाद में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत सरकार की ओर से शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए नई दिल्ली में ईरानी दूतावास का दौरा किया था। अभी यह पता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं। इसके पहले मई 2024 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर

दुर्घटना में मौत के बाद भारत ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसकी अगुवाई जगदीप धनखड़ ने की थी।

4 जुलाई से शुरू होंगे अंतिम संस्कार कार्यक्रम

अली खामेनेई का लंबे समय तक चलने वाला संस्कार उनकी मौत के चार महीने बाद किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मोसाला कॉम्प्लेक्स में शव को अंतिम दर्शन के लिए रखे जाने के साथ होगी। इसके बाद तेहरान और कोम शहरों में सार्वजनिक जुलूस निकाले जाएंगे। इराक के पवित्र शहरों नजफ और कर्बला में उनके लिए प्रार्थनाएं पढ़ी जाएंगी।

14 लाख सालाना कमाने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा मेंटिनेंस

हाईकोर्ट ने कहा- भरण-पोषण जरूरतमंद के लिए यह मांग पति से 'एक पाउंड मांस' वसूलने जैसी

जबलपुर (नप्र)। भोपाल की रहने वाली एक महिला की ओर से पति से अंतरिम भरण-पोषण (मेंटिनेंस) की मांग को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति को भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक 'मर्चेंट ऑफ वेनिस' का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि यह मांग पति से एक पाउंड मांस वसूलने के प्रयास जैसी प्रतीत होती है, जिसकी अनुमति न्यायालय नहीं दे सकता। मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने की। महिला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें तलाक संबंधी लंबित प्रकरण के दौरान अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमे के खर्च की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था।

2022 में हुई थी शादी, 2023 से अलग रह रहे- दंपति का विवाह 4 नवंबर 2022 को हुआ था। 2023 से दोनों अलग रह रहे हैं। पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी, जबकि पत्नी ने अंतरिम भरण-पोषण की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने 18 फरवरी 2026 को आदेश दिया था कि तलाक प्रकरण लंबित रहने के दौरान महिला को कोई मेंटिनेंस नहीं दिया जाएगा। इसी आदेश को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

पहले 20 लाख, अब 14 लाख सालाना आय का दावा- महिला ने अदालत में स्वीकार किया कि वह नौकरी करती हैं। पहले उनकी वार्षिक आय लगभग 20 लाख रुपए थी, जबकि पति की आय 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई थी। बाद में महिला ने कहा कि उनकी आय घटकर करीब 14 लाख रुपए सालाना रह गई है, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

नौरादेही-रिजर्व में बाघ के हमले से पहले चली थी गोली?

आरटीआई एक्टिविस्ट ने शेयर किया वीडियो, एपीसीसीएफ बोले-होगी जांच, एक ग्रामीण हुआ था घायल

भोपाल (नप्र)। नौरादेही बाघ अभयारण्य में बाघ के हमले में घायल व्यक्ति के मामले में चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो बाघ की तरह गोली चलाई गई हो। वीडियो में बाघ के सामने से गोली जैसी चीज निकलते दिख रही है। इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या नौरादेही बाघ अभयारण्य के मोहली रेंज में किसी बाघ की तरफ गोली चलाई गई थी, जिसके बाद उसने एक स्थानीय ग्रामीण पर हमला कर दिया।

यह घटना उस गांव की है, जिसे अभयारण्य घोषित किए जाने से पहले वन्यजीव आवास क्षेत्र घोषित होने के कारण विस्थापन के लिए चिह्नित किया गया था, लेकिन आज भी गांव के लोग वहीं रह रहे हैं। बाघ पर गोली चलने की आशंका के बीच इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की जा रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने यह वीडियो एक्स पर अपलोड किया है और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रधानमंत्री कार्यालय, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी,केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री समेत अन्य एजेंसियों से की है।एक

वीडियो सामने आया है। जिसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो बाघ की तरह गोली चलाई गई हो।वीडियो में ऐसा लग रहा है बाघ को हमला करने के लिए उकसाया गया हो।

दुबे ने एक्स पर लिखा है कि पटना मोहली गांव अभयारण्य क्षेत्र में आता है। इस गांव के विस्थापन के लिए निधि जारी होने के बावजूद अब तक इसे विस्थापित क्यों नहीं किया गया? इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है।

दुबे का कहना है कि सामने आए वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि बाघ को स्थानीय ग्रामीण पर हमला करने के लिए उकसाया गया हो। अत्यंत विश्वसनीय सूत्रों द्वारा साझा किए गए वीडियो में लगभग तीन सेकंड के आसपास संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि घटना के समय गश्ती वनकर्मी कहां थे। आरटीआई एक्टिविस्ट दुबे के अनुसार, वन विभाग का यह दावा कि युवक पर शौच के दौरान हमला हुआ, पूरी तरह मनगढ़ंत प्रतीत होता है। सच्चाई क्यों छिपाई जा रही है? उन्होंने कहा कि यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अतीत में इसी अभयारण्य से एक रेडियो कॉलर लगा बाघ रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था।

सोमवार की घटना, एपीसीसीएफ बोले- जांच कराएंगे

पटना मोहली गांव में यह घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया था कि बाघ ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया था। इस मामले में एपीसीसीएफ (वन्यजीव) एल. कृष्णमूर्ति का कहना है कि वीडियो देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि बाघ को कुछ मारा गया है। उसे पत्थर मारा गया है या कोई अन्य वस्तु, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है और मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय रेंज ऑफिसर और एसडीओ मौके पर पहुंच गए हैं।

एक तरफ प्यार, दूसरी ओर 'हत्या' की साजिश

पुणे मर्डर कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस भी हैरान

पुणे (एजेंसी)। पुणे में मंगेतर की हत्या करने वाली 20 साल की सिया गोयल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर

- मंगेतर केतन के साथ सिया की कई रोमांटिक पोस्ट

केतन अग्रवाल (26) के साथ कई रोमांटिक पोस्ट किए थे। कभी प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल, तो कभी डांस और गले मिलने के वीडियो। दोनों की नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियां भी सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा थीं। इस साल फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था- मेरे दिल को उसका घर मिले एक महीना पूरा हुआ। उसने केतन को टैग भी किया था। पुलिस के मुताबिक, 18 जून को केतन की मौत के दिन लोहगढ़ किले पर एक युवक हुडी पहनकर आया था।

बर्थडे पर केतन ने पहले से सेलीब्रेशन शुरू कर दिया

सोशल मीडिया पर सिया और उसके मंगेतर केतन का रिश्ता किसी परफेक्ट लव स्टोरी जैसी थी। 19 जून को सिया का बर्थडे था। केतन ने एक महीने पहले यानी 19 मई से ही काउंटडाउन सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था। वह रोज उसे अलग-अलग तरीके से अपनी मंगेतर सरप्राइज देता। सिया सोशल मीडिया पर इसके वीडियो पोस्ट करती थी। ये पोस्ट अब वायरल हो रहे हैं। एक पोस्ट में केतन अपनी कार फूलों से सजाकर सिया को गिफ्ट देता दिखा। सिया ने इसका वीडियो पोस्ट कर लिखा- उसने पसंद है तुम्हें वाली बात को बहुत सीरियसली से ले लिया।

भरत तिवारी के लिए बिहार में जुट गई हजारों की भीड़

भोजपुर के बिलौटी में महापंचायत, प्रशांत किशोर भी पहुंचे

आरा (एजेंसी)। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर रविवार को शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में आयोजित महापंचायत राजनीतिक और सामाजिक रूप से बड़ा केंद्र बनती जा रही है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह से ही दूर-दूर से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। गांव और आसपास के इलाकों में भरत तिवारी के पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं, जबकि कई लोग तिरंगा लेकर और नारेबाजी करते पहुंच रहे हैं। महापंचायत को लेकर सबसे अधिक उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है। आयोजन स्थल पर अब तक पांच हजार से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में किशोर और

युवा वर्ग के लोग न्याय की मांग को लेकर एकजुट नजर आए। इसी बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी महापंचायत में बिलौटी गांव पहुंच गए।

एलओसी पर 35 ड्रोन यूनिट तैनात, जंग छेड़ने की धमकी

- भारत के खिलाफ साजिश रच रहे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, तो पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने यह मसला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी लेकिन वहां भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को जंग छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। वहीं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुटे हैं। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की हैं। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैयार किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी सीमाओं से एलओसी में तैनात किया है।

चीन 5वीं जेनरेशन का फाइटर जेट देगा

ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को 36 मल्टी रोल जे-सीरीज फाइटर जेट की सप्लाई की है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी एफ-35 जेट का चीनी वर्जन जे-35 भी साल के अंत तक पाकिस्तान को मिलने वाला है। इस जेट की टेस्ट फ्लाइट्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने के बाद अब तुर्किये कराची के पास साझा कॉम्बैट ड्रोन असेंबली प्लांट भी लगाया है। यहां हर साल 700 ड्रोन बनेंगे। पाकिस्तान ने इन ड्रोन को बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का एमओयू भी किया है। तुर्किये पाकिस्तान के लिए मिलजैम क्लास पनडुब्बी भी बना रहा है। पाकिस्तान को पनडुब्बी की साल के अंत तक डिलीवरी भी मिल जाएगी।

रक्षा मंत्री बोले थे-भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तानी चैनल से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है।

पाक एयरस्पेस में घुसा एअर इंडिया का विमान

- दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ा, तकनीकी खराबी से रास्ता भटका

अमृतसर (एजेंसी)। एअर इंडिया की एक फ्लाइट सोमवार रात रास्ता भटककर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसी। इसे पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर वापस भेजा। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और इसे अमृतसर लैंड होना था। पाकिस्तान के एयर स्पेस से जब फ्लाइट लौटी तब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ गया था, ऐसे में इसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि तकनीकी खराबी के कारण यह फ्लाइट रास्ता भटक गई थी। मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले 12 जून को पाकिस्तान की भी पैसेंजर फ्लाइट फ्लाई जिन्ना-9 के 514 खराब मौसम के कारण भारतीय एयरस्पेस में घुस आई थी।

गुणवत्ता की निगरानी के मानक मापदंड किए जाएं निर्धारित : राज्यपाल पटेल

राज्यपाल ने सिकल सेल उन्मूलन अभियान की प्रगति पर हर्ष व्यक्त किया

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि योजनाओं की मंशा और क्रियान्वयन की व्यवहारिकता में संवेदनशीलता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के मानक मापदंड निर्धारित किए जाए। अधिकारियों द्वारा निगरानी मापदंड के अनुसार नियमित गुणवत्ता परीक्षण करना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल लोक भवन में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल को बैठक में पीएम-जनमन योजना अंतर्गत 9 विभागों की 11 अधोसंरचनात्मक, 7 हितग्राही मूलक योजनाओं और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की 25 योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की पहल पीएम-जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजनाएं है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के लिए निर्धारित समय सीमा तक कार्य की रीति-नीति उचित नहीं है। रणनीति, समय सीमा से पहले कार्य पूरा करने की होनी चाहिए। नए कार्यों के क्रियान्वयन में पूर्व अनुभवों और चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना तैयार की

जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अति पिछड़ी जनजातियों के विकास और उत्थान के प्रयासों को आवश्यकता और बहुलता की प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन की औपचारिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

राज्यपाल श्री पटेल ने प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन अभियान के तीव्र गति से क्रियान्वयन पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 से पूर्व वर्ष 2026 तक लक्ष्य का पूरा होना अनुमानित है। उन्होंने सभी संबंधितों को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष की आयु तक के सिकल सेल रोगी वाहक के स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे उनका भावी जीवन सुरक्षित हो जाएगा। जरूरी है कि सिकल सेल की दवाओं की उपलब्धता सदैव सुनिश्चित रहे। एलोपैथिक उपचार पद्धति के साथ ही आयुर्वेद औषधियों के उपयोग के संबंध में जन जागरण के प्रयासों की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की दवाओं के उपयोग से रक्त की उपलब्धता बढ़ने और थकान में कमी के उत्साह जनक प्रारंभिक परिणाम प्राप्त हुए है। राज्यपाल ने बैठक में जनजातीय बहुल क्षेत्रों की तहसीलवार बुनियादी सुविधाओं का मानचित्र तैयार कर प्रभावी निगरानी, जन औषधि केन्द्रों के संचालन में जनजातीय युवाओं की भागीदारी तथा विद्यालयों में छात्राओं, छात्र के पृथक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया।

समीक्षा बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा, जनजातीय प्रकोष्ठ की सदस्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी सिंह, प्रकोष्ठ के सदस्य, लोक भवन और जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने वीरांगना रानी दुर्गावती को दी श्रद्धांजलि

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उनको नमन किया। उन्होंने लोकभवन में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल श्री पटेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर दो मिनट का मौन धारण किया। रानी दुर्गावती का पुण्य स्मरण कर नमन किया। लोकभवन के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, लोकभवन एवं जनजातीय प्रकोष्ठ के सदस्य, अधिकारी गण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरांगना रानी दुर्गावती का शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। रानी दुर्गावती ने मुगलों को भी लोहे के चने चबवा दिये। एक युद्ध में वीरांगना रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। इतिहास में उनका राष्ट्रप्रेम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, जो हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा।

विंध्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को मिलेगा उत्कृष्ट मंच

रीवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक होगा विकसित

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के लिए विश्वस्तरीय खेल अधोसंरचना का विकास समय की आवश्यकता है। उन्होंने रीवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विंध्य क्षेत्र में आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास से खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा। इससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को अपनी

क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा तथा वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स रीवा के विकास कार्यों की समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने खेल अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाने तथा खिलाड़ियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रीवा में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण क्षेत्र में एथलेटिक्स गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री संजीव कुमार सिंह उपस्थित थे।

व्यंग्य कवि सुनील चतुर्वेदी को सरस्वती प्रभा सम्मान

भोपाल। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था प्रभात साहित्य परिषद, भोपाल द्वारा व्यंग्य कवि और पैरोडीकार सुनील चतुर्वेदी को राजधानी के हिन्दी भवन में सरस्वती प्रभा सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान पिछली काव्य गोष्ठी में पढ़ी गई उनकी रचना के लिए दिया गया है, जिसका

चयन संस्था की चयन समिति द्वारा गया था । सम्मान समारोह के मुख्यातिथि साहित्यकार बलराम गुमाश्ता, अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह और रमेश नंद ने श्री चतुर्वेदी को शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया । इस समारोह में वरिष्ठ गीतकार अशोक निर्मल, मनोज जैन, डॉ राजेश तिवारी, अशोक व्यास, अनिता तिवारी, अशोक धमैनियां, सुरेश पबरा सहित बड़ी संख्या में रचनाकार मौजूद थे ।

युवक ने सेक्स करने से मना किया तो की हत्या

भोपाल में आरोपी युवक बोला- खाना खिलाया था मैंने, वो मांग पूरी नहीं कर रहा था

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मिले युवक के अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने युवक के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। विरोध करने पर उसने पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मृतक का मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

कटारा हिल्स थाना पुलिस के मुताबिक 24 मई को इकोलॉजिकल पार्क के पास पुलिया किनारे एक युवक का कई दिन पुराना शव मिला था। शव की हालत खराब होने के कारण उसकी पहचान करने में समय लगा। बाद में पुलिस ने मृतक की पहचान भोपाल निवासी के रूप में की, जो मंडीदीप स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मोबाइल फोन ने खोला हत्या का राज

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक का मोबाइल फोन गायब है। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो वह एक व्यक्ति के पास मिला। पूछताछ में उस व्यक्ति ने बताया कि उसने मोबाइल अजय मायना नाम के युवक से खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने अजय मायना को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया।

पहले खाना खिलाया, फिर पुलिया के नीचे ले गया

पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि घटना वाली रात वह शिकार की तलाश में घूम रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नशे की हालत में मिले युवक से हुई। आरोपी ने पहले उसे खाना खिलाया और फिर अपने साथ पुलिया के नीचे ले गया। वह युवक के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन युवक ने इसका विरोध किया। इस बात से नाराज होकर आरोपी ने पत्थर से उसके सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया।

न्यू मार्केट और वीआईपी रोड पर भी तलाशता रहा साथी

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना से पहले वह न्यू मार्केट और वीआईपी रोड इलाके में काफी देर तक घूमता रहा। वहां उसे कोई नहीं मिला तो वह मिसरोद स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे एक युवक मिला था।

पहले भी जा चुका है जेल

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अजय मायना पहले भी एक युवक के साथ गलत काम करने के मामले में जेल जा चुका है। उस मामले में वह करीब तीन महीने तक जेल में रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है। उसके व्यवहार और मानसिक स्थिति के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

उद्धव ठाकरे के लिए गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं

केंद्रीय मंत्री ने कहा- एनडीए में आने का रास्ता है, बाहर जाने का नहीं

इंदौर (नप्र)। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को इंदौर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। अठावले ने कहा- उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का राजनीतिक आधार लगातार कमजोर हो रहा है और उनके कई सांसद तथा विधायक एनडीए में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं।

उद्धव के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं

अठावले ने कहा कि अगर कोई नेता एनडीए में आता है तो उसका स्वागत किया जाएगा और भविष्य में उद्धव ठाकरे के लिए भी गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं हैं। रामदास अठावले ने कहा कि राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को अधिक समर्थन मिल रहा है जबकि उद्धव ठाकरे गुट की ताकत पहले की तुलना में कमजोर हुई है। कई जनप्रतिनिधि और नेता एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं और गठबंधन में शामिल होने के लिए रास्ते हमेशा खुले हुए हैं।

एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं ठाकरे

अठावले ने अपने खास अंदाज में कहा कि एनडीए में आने के लिए सभी का स्वागत है लेकिन यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं और ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद उद्धव ठाकरे भी भविष्य में एनडीए का हिस्सा बन जाएं। इस दौरान उन्होंने शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता और सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधा। अठावले ने कहा कि संजय राउत केवल बयान देने के लिए जाने जाते हैं और उनकी भूमिका बयानबाजी तक ही सीमित है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हफ्ते भर में घोषित होंगे बचे हुए एल्डरमैन

भोपाल-इंदौर समेत 16 नगर निगमों सहित 244 नगरीय निकायों में नियुक्त होंगे मनोनीत पार्षद

भोपाल (नप्र)। एमपी में हफ्ते भर में नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति हो सकती है। सीएम डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच मंथन पूरा हो चुका है। संभवतः इसी हफ्ते में बचे हुए निकायों में एल्डरमैन घोषित करने की तैयारी है। प्रदेश के करीब 244 नगरीय निकायों में मनोनीत पार्षदों यानी एल्डरमैन की नियुक्ति होना बाकी है।

नगर निगमों में नियुक्त होंगे एल्डरमैन- एमपी के 16 नगर निगमों में 12-12 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जबलपुर सहित सभी नगर निगमों के एल्डरमैन के लिए संभावित नामों की लिस्ट जिला स्तरीय कोर ग्रुप में चर्चा के बाद प्रदेश संगठन को भेजे जा चुके हैं। दो बड़े शहरों में कुछ नामों पर चर्चा अंतिम दौर में है।

इन नगर निगमों में नियुक्त होंगे मनोनीत पार्षद- भोपाल,इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर,उज्जैन,सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, मुरैना, छिंदवाड़ा, देवास,कटनी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर।

मार्च में 169 निकायों में नियुक्त हुए थे एल्डरमैन- मार्च में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। इन नियुक्तियों में विशेष रूप से नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को कवर किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है।

यात्रियों की सुविधा हेतु सोगरिया-धनबाद-सोगरिया साप्ताहिक विशेष रेलसेवा की संचालन अवधि में विस्तार

भोपाल। अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 09821/09822 सोगरिया-धनबाद-सोगरिया साप्ताहिक विशेष रेलसेवा की संचालन अवधि में विस्तार किया गया है। इस विशेष रेलसेवा के संचालन अवधि विस्तार से पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के रूठियाई, गुना एवं अशोकनगर स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 09821 सोगरिया-धनबाद साप्ताहिक विशेष रेलसेवा का संचालन पूर्व निर्धारित अवधि के बाद अब 26 नवम्बर 2026 तक बढ़ाया गया है। यह रेलसेवा प्रत्येक गुरुवार को संचालित होगी। पूर्व में इसका संचालन 16 जुलाई 2026 तक अधिसूचित था। संचालन अवधि में विस्तार के फलस्वरूप यह रेलसेवा कुल 20 अतिरिक्त ट्रिप संचालित करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09822 धनबाद-सोगरिया साप्ताहिक विशेष रेलसेवा का संचालन 28 नवम्बर 2026 तक बढ़ाया गया है। यह रेलसेवा प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी। पूर्व में इसका संचालन 18 जुलाई 2026 तक अधिसूचित था। विस्तार अवधि के दौरान यह रेलसेवा भी कुल 20 अतिरिक्त ट्रिप संचालित करेगी। यह विशेष रेलसेवा अपने वर्तमान समय, ठहराव एवं रेक संरचना के अनुसार संचालित होती रहेगी। भोपाल मंडल के यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी रेलवे की अधिकृत वेबसाइट, एनटीईएस, रेलवे हेल्पलाइन 139 अथवा निकटतम रेलवे स्टेशन से प्राप्त कर लें।

मण्डल रेल चिकित्सालय, निशातपुरा ने स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण किए

भोपाल। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल स्थित मण्डल रेल चिकित्सालय, निशातपुरा ने आज अपनी स्थापना के 30 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए। इस अवसर पर चिकित्सालय परिसर में 'स्थापना दिवस' समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

उल्लेखनीय है कि मण्डल रेल चिकित्सालय, निशातपुरा की स्थापना 24 जून 1996 को की गई थी। विगत तीन दशकों से यह चिकित्सालय रेल कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा रेलवे की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय डोगरा ने चिकित्सालय की 30 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे भविष्य में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी, निष्ठा एवं समर्पण के साथ करते रहें तथा रोगियों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्कृष्ट स्वास्थ्य

सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लें। इस अवसर पर चिकित्सालय की प्रगति एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया। समारोह में कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (प्रशासन) डॉ. रचना श्रीवास्तव, चिकित्सकगण, सहायक नर्सिंग अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ तथा चिकित्सालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। स्थापना दिवस समारोह का समापन चिकित्सालय परिवार द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा रोगी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के साथ हुआ।

भोपाल मंडल में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान

22 टीकाकरण बूथ एवं मोबाइल टीमों के माध्यम से बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक

भोपाल। बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने एवं राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल में डीआरएम श्री पंकज त्यागी के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ अजय डोगरा के निर्देशन में दिनांक 28, 29 एवं 30 जून 2026 को विशेष पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत भोपाल मंडल में कुल 22 पोलियो टीकाकरण बूथ स्थापित किए गए हैं। मंडल के प्रमुख स्टेशनों भोपाल, इटारसी, बीना, गुना, गंजबासौदा सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर टीकाकरण बूथ संचालित किए जाएंगे, जहां 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी।

यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों के बच्चों तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष मोबाइल टीमें भी गठित की गई हैं। ये टीमें बीना दिशा में संचालित झेलम एक्सप्रेस, पंजाब मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एवं राजकोट एक्सप्रेस तथा इटारसी दिशा में संचालित कर्नाटक एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस एवं उज्जैन दिशा में संचालित मालवा एक्सप्रेस सहित विभिन्न ट्रेनों में यात्रा कर रहे बच्चों को चलती ट्रेनों में पोलियो की दवा पिलाएंगी। इसके अतिरिक्त मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले रेल कर्मचारियों एवं आसपास के नागरिकों के बच्चों की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेनों तथा रेलवे कॉलोनियों में भी विशेष टीकाकरण व्यवस्था की गई है। पैसेंजर ट्रेनों के माध्यम से प्रत्येक स्टेशन पर रुक-रुक कर बच्चों को पोलियो की खुराक प्रदान की जाएगी।

रेल प्रशासन सभी रेल कर्मचारियों, यात्रियों एवं आम नागरिकों से अपील करता है कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को इस अभियान के दौरान पोलियो की दवा अवश्य पिलवाएं तथा स्वस्थ एवं पोलियो मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

उज्जैन में फोटो एडिट कर किया गया था वायरल, एक फरार

नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल, बीएलओ सहित 4 गिरफ्तार

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन की पंवासा थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा की फोटो का दुरुपयोग कर उसे अश्लील वीडियो में जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस के अनुसार पूरी साजिश नाबालिग को बदनाम करने के मकसद से रची गई थी।

पीड़िता के पिता ने 21 जून 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के नाम से तीन अश्लील वीडियो गांव और समाज के व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल किए गए, जिससे गांव में अफवाह फैल गई कि वीडियो में दिखाई दे रही युवती उनकी बेटी है। इससे नाबालिग की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उसे बदनाम करने की कोशिश की गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि वीडियो में दिखाई दे रही युवती पीड़िता नहीं थी। किसी दूसरी लड़की के अश्लील वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसमें पीड़िता की फोटो एडिट कर लगाई गई थी। साइबर सेल की जांच में पता चला कि पीड़िता की पासपोर्ट साइज फोटो नवंबर 2025 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जमा किए गए फॉर्म से निकाली गई थी। आरोप है कि संबंधित बीएलओ फखरुनिशा उर्फ बेबी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यह फोटो आरोपी एहसान पटेल को व्हाट्सएप पर भेज दी। इसके बाद एहसान पटेल, आबिद पटेल और मुजफ्फर पटेल ने फोटो आपस में साझा की। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फर पटेल ने तकनीक का गलत इस्तेमाल कर फोटो को एडिट किया और आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूछताछ में उसका नाम वीडियो एडिट करने वाले मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मूल अश्लील वीडियो किसने उपलब्ध कराया था।

फोटो एडिट करके लगाई

चार गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79, 49 और आईटी एक्ट की धारा 67(ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। घटना में इस्तेमाल किए गए चार मोबाइल फोन और एसआईआर से जुड़े सरकारी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में आबिद पटेल (देवास), मुजफ्फर पटेल (उज्जैन), एहसान पटेल (उज्जैन) और बीएलओ फखरुनिशा शामिल हैं। फरार आरोपी यूसुफ पटेल की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

पुलिस का कहना है कि पीड़िता नाबालिग है और उसका आरोपियों से कोई विशेष संबंध नहीं है। सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं और खेती-बाड़ी का काम करते हैं। प्रारंभिक जांच में यह मामला किसी को सामाजिक रूप से नीचा दिखाने और बदनाम करने की सोची-समझी साजिश प्रतीत हो रहा है।

संपादकीय

स्टार्मर के इस्तीफे की वजहें

दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले और कभी आधी दुनिया पर राज करने वाले ग्रेट ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वहां के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने उनके नेतृत्व को लेकर अपनी ही लेबर पार्टी के सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। लेबर पार्टी के सांसदों ने सवाल किया था कि क्या स्टार्मर अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही हैं। इस पर पद से इस्तीफा देते हुए स्टार्मर ने कहा कि मैंने इस सवाल पर अपनी पार्टी का 'जवाब सुन लिया है' और 'उस जवाब को अच्छे से स्वीकार करता हूं। मैंने जो भी फैसला लिया है, वह अपने देश को सबसे पहले रखने' के बारे में रहा है, जिससे वह प्यार करते हैं। पार्टी का अंदरूनी दबाव महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफे देने की बात क्यों कहीं, खासकर तब कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे उन्होंने झुकने से मना कर दिया था, ऐसे में कौन सी मुख्य वजह थी, जिसके लिए इस्तीफा दिया, इस बारे में विश्लेषक अलग अलग कारण बता रहे हैं। ब्रिटेन में नए नेतृत्व के लिए चुनाव अगले महीने होगा। तब तक स्टार्मर अपने पद पर बने रहेंगे। बताया जाता है हाल में हुए उपचुनाव में मेकरफ़ील्ड उपचुनाव में एंडी बर्नहैम की शानदार जीत के बाद किएर स्टार्मर से डाउनिंग स्ट्रीट से अपने जाने का टाइम टेबल तय करने के लिए कहा जा रहा था। लेबर पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद किएर स्टार्मर से कह रहे थे कि वे ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर को सत्ता सौंपने के प्लान की घोषणा करें। जाहिर है कि एंडी बर्नहैम 9 जुलाई को मुकाबला शुरू होने पर बिना किसी चुनौती के चुनाव लड़ते हैं, तो नॉमिनेशन बंद होने के बाद वो लेबर लीडर बन सकते हैं। गौरतलब है कि किएर स्टार्मर अप्रैल 2020 में लेबर पार्टी के नेता चुने गए और लेबर की आम चुनाव में जीत के बाद 5 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन को जल्द ही 2016 के बाद से अपना सातवां प्रधानमंत्री मिलेगा। स्टार्मर ने अपने इस्तीफ़े की घोषणा करने से पहले कहा कि उन्हें विरासत में लेबर पार्टी मिली थी जो 'पॉलिटिकली, फ़ाइनेंशियली और नैतिक रूप से दिवालिया' थी। उन्होंने दावा किया कि मैंने 'एंटीसेमिटिज़्म के ज़हर को निकालकर' पार्टी को बदल दिया। दरअसल शुरुआत से ही सर किएर स्टार्मर के कार्यकाल में समस्याओं के संकेत दिखाई देने लगे थे। प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ तीन महीने बाद ही उन्हें 6000 पाउंड से अधिक मूल्य के उपहारों और मेहमाननवाज़ी का ख़र्च वापस करना पड़ा, जो उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला था। इनमें टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट के टिकट भी शामिल थे। स्टार्मर को कई नीतिगत यू-टर्न के लिए भी कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। साथ ही दक्षिणपंथी वर्ग ने भी उनकी आलोचना की, क्योंकि वे फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार कर अवैध रूप से ब्रिटेन आने वाले प्रवासियों की संख्या को रोकने में असफल दिखाई दिए। जनमत सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं ने लगातार पाया कि किएर स्टार्मर जनता के बीच बेहद अलोकप्रिय हो गए थे। उनकी लोकप्रियता रेटिंग रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गई थी। इसके अलावा स्टार्मर ने एपस्टीन के करीबी लॉर्ड मेंडेलसन को ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। स्टार्मर की रवानगी के पीछे बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के ट्रंप के न्यौते को ठुकराने से अमेरिका उनसे नाराज हो गया। हालांकि बाद में ब्रिटेन ने अपने सैन्य अड्डों के उपयोग की इजाजत दे दी थी। लेकिन बात नहीं।

नजरिया

अनुराग बेहार

लेखक अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ एवं अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संस्थापक वाइस चांसलर हैं।

अंग्रेजी अखबार मिंट में प्रकाशित आलेख अनुदित

ज्ञान का भ्रम पैदा करते स्कूली पाठ्यक्रम की दिशा

मनुष्य का ज्ञान बढ़ रहा है। इंसानियत की अब तक संचित समझ भी हर क्षेत्र में गहरा रही है, बढ़ रही है। निस्संदेह ही यह उत्सव मनाने वाली बात है पर यह स्कूली शिक्षा के लिए एक गंभीर और लगभग नज़रअंदाज़ कर दी जाने वाली समस्या भी पैदा करता है। जब शिक्षा व्यवस्था के ऊपर यह दबाव रहता है कि वह इस लगातार बढ़ते ज्ञान को बच्चों तक पहुँचाए तो उसके लिए पाठ्यक्रम को भी विस्तारित होना पड़ेगा, लेकिन स्कूली शिक्षा की समयावधि सीमित होती है, स्कूली शिक्षा 12 साल की होती है।

इसका नतीजा यह है कि भारत समेत कई देशों के स्कूलों में पाठ्यक्रम अत्यधिक विस्तृत और स्तराधिक सघनता लिए हुए दिखाई देता है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी तय समयावधि वाले विद्यालयीन जीवन में ऐसी कितनी ही जटिल सैद्धान्तिक विषयवस्तु से गुज़रते हैं, जिसमें वे अवधारणाएँ भी शामिल हैं जिन्हें कभी महाविद्यालय के स्तर पर पढ़ाया जाता था। पाठ्यक्रम का बढ़ता हुआ आकार आश्चर्यजनक है पर इससे सीखने में मदद मिलती है या नहीं, यह दूसरा सवाल है।

विषयवस्तु और सीखने के बीच का रिश्ता क्रमिक नहीं है। अधिक विषयवस्तु का अर्थ ज्यादा सीखना है, यह एक हद तक ही सच है। इसके बाद तो ढेर सारी विषयवस्तु का अर्थ है किसी एक विचार पर ठहरने के लिए कम समय उपलब्ध होना। यानी यह विषयवस्तु कक्षा में इतनी तेजी से और इतने सतही तरीके से पढ़ाई जाती है कि उस पर सही समझ विकसित करना नामुमकिन हो जाता है और फिर बच्चे और टीचर सिर्फ़ एक ही तरीका अपनाते हैं जो काम करता है यानी रट्टा मारना, जो पाठ्यक्रम ज्ञानवर्धन के लिए बनाया था, वह अब केवल ज्ञान का भ्रम पैदा करता है।

शिक्षा के क्षेत्र में हुए शोध लगातार दिखाते हैं कि पाठ्यक्रम के अत्यधिक विस्तृत होने से विद्यार्थी इसे केवल सतही तौर पर समझ पाते हैं यानी तथ्यों की विवेचना और विश्लेषण (जो कि तार्किक सोच के निर्माण का आधार है) किए बिना केवल उन्हें याद रखते जाते हैं। यह किसी एक विद्यार्थी या शिक्षक की नाकामी नहीं है, बल्कि यह विकास के कई आयामों में बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने का एक संरचनात्मक परिणाम है। यह ठीक है कि विषयवस्तु और क्षमताओं का विकास एक-दूसरे के उलट नहीं हैं-एक बच्चा खालीपन में सोचना नहीं सीख सकता, उसे सोचने के लिए विषयवस्तु की ज़रूरत होती है लेकिन जब विषयवस्तु अत्यधिक विस्तृत और सघन हो जाए तो उस पर सोचने जैसी इंसानी काबिलियत के लिए कोई जगह नहीं बचती। सब कुछ रटने, याद करने में बदल जाता है।

सभी प्रमाण इस बात को और पुष्ट करते हैं।

अतिभारित पाठ्यक्रम को लेकर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD 2020) द्वारा किए गए अध्ययन में पाया कि कई देश पाठ्यक्रम को राजनीतिक, वैचारिक और अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुरूप विस्तार देने या अतिभारित करने के तनाव से जूझ रहे हैं। यह दबाव पाठ्यक्रम से जुड़ाव बनाने और उसे गहराई से समझने की प्रक्रिया को कम करता है और सीखना कठिन बनाता है। पाठ्यक्रम के विस्तार और सघनता पर ध्यान देना और सुसंगति बनाए रखना इस शोध की प्रमुख अनुशंसाएँ हैं जो अन्य गंभीर शोधों की अनुशंसाओं में भी ध्वनित होती दिखाई देती हैं।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस समस्या का सीधा सामना किया। इसमें पाठ्यक्रम को लेकर जो मुख्य कमियाँ बताई गईं, उनमें रटवाना और विषयवस्तु का अतिभारित होना शामिल था। इसके लिए नीति में विषयवस्तु पर केन्द्रित रहने की बजाय दक्षताओं के विकास की ओर बढ़ने, शिक्षा के स्तर को बच्चों के वास्तविक सीखने के तरीकों से जोड़ने और समझ विकसित करने के लिए समय और स्थान देने के स्पष्ट सुझाव दिए गए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 ने इसे पाठ्यचर्या अवधि के अनुरूप रेखांकित किया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पाठ्यक्रम को दक्षता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए और विषयवस्तु का अतिभार कम किया जाना चाहिए। यह वर्तमान में मौजूद रटंत संस्कृति और केवल स्मृति आधारित परीक्षा प्रणाली से आगे बढ़कर ऐसे तरीकों की बात करता है जो समस्या समाधान, तार्किक सोच और सीखने के लिए आवश्यक दक्षताएँ विकसित करें और उन दक्षताओं का आकलन कर सकें।

इन सभी अनुशंसाओं को लागू करने में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। एक फ्रेमवर्क बदलाव की बात कर सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम की संरचना, पाठ्यपुस्तकें, कक्षा शिक्षण प्रक्रियाएँ और आकलन में तालमेल बनाए बिना यह बदलाव केवल कागज़ों पर सिमट कर रह जाएगा।

जिन शिक्षकों ने अपना पूरा शैक्षणिक जीवन केवल पाठ्यक्रम पूरा करने में बिताया है, उन्हें इस तरह का बदलाव लाने के लिए लगातार सहयोग की ज़रूरत होगी, सिर्फ़ कागज़ी निर्देश काफ़ी नहीं होंगे। अभिभावक जिनका शिक्षा का अनुभव सिर्फ़ अच्छे अंक लाने और विषयवस्तु रटने तक सीमित था, उन्हें भी साथ लाना होगा। उन्हें रुकावट मानकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इसी तरह पाठ्यक्रम तैयार करने वाले विशेषज्ञों को अपने विषय को अधिक अहमियत देने की ओर आकर्षित होने से बचना होगा यानी उस सोच से बचना होगा जो कहती है- लेकिन बच्चों को यह भी सिखाना ही चाहिए।

बच्चों को सब कुछ सिखा देना चाहिए, यह सोच ही समस्या की जड़ है और यह सोच पूरी तरह से इंसानी है। पाठ्यपुस्तक लिखने वाली कमेटी में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो यह कहने में सहज महसूस करते हैं कि यह अवधारणा इस आयु में सिखाने लायक नहीं है। पाठ्यक्रम में कुछ भी छोड़ा जाना सीखने के एक मौके का छूट जाना लगता है लेकिन यही वह फ़ैसला है जिसकी अच्छे पाठ्यक्रम निर्माता को ज़रूरत होती है। पाठ्यक्रम निर्माता को भरोसा होना चाहिए कि बहुत सारी जानकारी को खराब तरीके से पढ़ाया जाए इसकी बनिस्बत कम विषयवस्तु को अच्छी तरह से पढ़ाने से ज़्यादा सीखने को मिलता है।

स्कूल की पढ़ाई का मकसद बच्चे के 18 साल का होने से पहले उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी ज्ञान दिया जाए यहाँ तक सीमित नहीं है। यह लक्ष्य हमेशा से ही हासिल नहीं हो पाया है और हर दशक में यह और भी मुश्किल होता जा रहा है। उद्देश्य यह है कि हर बच्चे में सीखने के क्षमता विकसित की जा सके जिससे वह ध्यान से पढ़ना, प्रमाण के आधार पर तर्क करना, अच्छे सवाल पूछना और जिज्ञासा बनाए रखना सीख सके। जो विद्यार्थी इन काबिलियतों के साथ स्कूल से निकलते हैं तो वे जिस जानकारी से भरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ वे लगभग वह सब कुछ सीख सकते हैं जो वे बाद में सीखना चाहते हैं या जिसे सीखने की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 ने इसे एक बुनियादी सिद्धान्त के तौर पर स्थापित किया है। अब इस सिद्धान्त को अमली जामा पहनाने के लिए इसका कक्षा, किताबों, परीक्षाओं और शिक्षकों की कक्षा प्रक्रियाओं में दिखाई देना सबसे ज़रूरी है। किसी सिद्धान्त को अमल में लाने का यह काम वास्तव में एक फ्रेमवर्क लिखने से ज्यादा धीमा और मुश्किल है पर यही एक ऐसा अकेला घटक है, जो स्कूल में बच्चों के साथ जो होता है उसे पूरी तरह से बदल देगा।

विपक्ष की आक्रामकता व मोदी की बढ़ती मुश्किलें

राजनीति

अनिल ठाकुर

लेखक स्तंभकार हैं।

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सीटों पर अटक जाने से यह कहा जाने लगा था कि मतदाता का मोदी से मोह भंग होने लगा है, वे विपक्ष के जाल में घिरे हुए नजर आने लगे। सरकार गठन तक कई आशंका, कुशंका व्यक्त होती रही। सरकार बनने के बाद भी कहा जाता रहा कि यह एक कमजोर एवं बैसाखी पर टिकी सरकार है इसका लंबे समय तक सत्ता में रहना मुश्किल है। अभी तक मोदी ने इन सभी संभावनाओं को झुठलाते हुए ऐसे निर्णय लिए जिससे यह सिद्ध हो गया कि सरकार एवं साथी दलों पर मोदी की मजबूत पकड़ है। बावजूद इसके कुछ ताजा घटनाकर्मों की वजह से मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, विपक्ष विशेष रूप से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ज्यादा आक्रामक है।

यूपी में 2027 में विधान सभा चुनाव होना है इसलिए अखिलेश के बयानों में व्यंग्य एवं तल्खी दोनों देखने को मिल रही है। बिहार और बंगाल के नतीजों से डरे हुए अखिलेश को अनायास राम मंदिर चंदा घोटाले प्रकरण से योगी एवं मोदी को एक साथ कटघरे में खड़ा करने का सुनहरा मौका मिल गया। राम मंदिर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 2014 में सरकार बनने के बाद से जिस तरह से मोदी ने न्यायिक निर्णय के माध्यम से इसे जमीन पर साकार किया वह अद्वितीय ही कहा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी की कुशल प्रशासकीय व्यवस्था एवं सतत् निगरानी का योगदान भी अमूल्य ही कहा जाएगा। स्थापना के इतने कम समय में रामलला के आंगन में करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप दी गई धन राशि, गहनों में घोटाले की खबर से सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश वासी सन्न रह गए। जांच कमेटी की रिपोर्ट, कार्यवाही लंबे समय तक चलेगी, निष्कर्ष चाहे जो आए लेकिन जिस तरह की भावनाएं व्यक्त की जा रही वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी नेताओं के बयान आग में घी का काम कर रहे है। इसकी थोड़ी बहुत भरपाई दोषियों को चिन्हित कर यूपी चुनाव के पूर्व कड़ी सजा देने के अतिरिक्त किसी तरह नहीं हो सकती। हिंदू वोट बैंक को विभक्त करने के लिए अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले के सफल प्रयोग को इस प्रकरण से बढ़ावा ही मिलेगा।

राम मंदिर चंदा घोटाला प्रकरण के कुछ दिन पूर्व नीट पेपर लीक मामले से युवाओं में असंतोष की जो व्यापक प्रतिक्रिया हुई, उसे सहज नहीं कहा जा सकता। सबसे अनोखी बात यह है कि इस घटना को सीजेआई के एक बयान से जोड़कर नई कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की माँग कर मोदी के लिए मुश्किल खड़ी की जा रही है। सरकार के सफलता पूर्वक नीट परीक्षा पुनः करवाने के बावजूद युवाओं में असंतोष है। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर काकरोच जनता पार्टी बनी थी, उसके प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए जो मुद्दे पर कम अन्य विवादित विषयों पर अधिक बात कर रहे है, जो एक मजाक बनता जा रहा है।

इन दो तात्कालिक मुद्दों के अलावा विपक्ष विशेष रूप से राहुल गांधी बिहार चुनाव के पहले से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के समय वोट चोरी के नए मुद्दे को लेकर न्यायपालिका तक गुहार लगाते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इन चुनावों के पहले तक वे ईवीएम हेक मुद्दे पर आक्रामक रहे थे। दुर्भाग्य से राहुल को बिहार में वोट चोरी पर ही अपने साथी दल राजद के नेता तेजस्वी यादव का समर्थन नहीं मिला। अमित शाह ने इसे बंगला देशी घुसपैठियों की पहचान से जोड़ कर हिन्दू वोट बैंक को एकजुट होने में सफलता प्राप्त कर ली। बिहार के बाद बंगाल चुनाव के समय ममता मुख्यमंत्री थी, उन्होंने दो मोर्चों पर इस लड़ाई को लड़ा। एक तो मतदाता सूची पुनरीक्षण में अपने मतदाताओं के असंख्य वोट जुड़वा दिए, दूसरा चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोपों को लेकर न्यायपालिका में खुद अपना पक्ष रखा, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर मोदी शाह को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उनके 15 वर्ष के कार्यकाल में मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ विधायकों की अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी से पीड़ित भद्र मानस का मन बदल गया। राहुल गांधी ने गठबंधन की साथी टीएमसी सरकार को भ्रष्ट बताकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। चुनाव में बुरी हार से बौखलाई ममता ने मोदी से बदला चुकाने के लिए देहली का रुख किया ही था कि उनके दो तिहाई विधायकों ने बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। कांग्रेस में विलय की खबरों को पार्टी सांसदों के ममता का सरेंडर मानने के वजह से दो तिहाई सांसदों ने भी एक नया आशियाना ढूंढ लिया। और अब शिवसेना उद्धव गुट के छह सांसद टूट कर पुराने साथी शिंदे गुट में शामिल होकर सरकार का हिस्सा बन गए। इस टूट का आरोप भी अमित शाह पर है, कानूनी पक्ष भी दिए जा रहे है। निर्णय जो भी हो फिलहाल बीजेपी की ताकत बढ़ रही मगर इसने विपक्ष को एक जुट होने में मदद जरूर की। बंगाल की हार के बाद ममता के आव्हान पर इंडी गठबंधन की बैठक आयोजित किया गया, मगर उसमें भी साथी दलों के नेताओं द्वारा कांग्रेस की कार्यशैली पर उंगली उठाने से एकजुटता के बजाय दरार नजर आई। लंबे विचार विमर्श के बाद भी सरकार के विरुद्ध संगठित रूप से किसी आन्दोलन की रूप रेखा बनाने के बजाय कुछ प्रस्ताव पारित कर दो महीने बाद पुनः मीटिंग आयोजित करने का निर्णय भर लिया गया। इससे साफ संदेश निकलता है कि राहुल गांधी सिर्फ 29 के चुनाव को केंद्रित कर क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूरन कांग्रेस में विलय कर स्वयं को प्रधानमंत्री पद का एकमात्र योग्य उम्मीदवार घोषित करना चाहते है। राहुल गांधी भविष्यवाणी कर चुके है कि अगले एक वर्ष में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन क्या वे यह कहना चाहते है कि एक वर्ष बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ?

अपने कार्यकाल के प्रारंभिक वर्षों से ही मोदी को चीन के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से डोकलाम, पुलवामा जैसी घटनाओं से निपटना पड़ा। पिछले वर्ष पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जाति पूछकर की गई नृशंस हत्या की घटना से ऑपरेशन सिंदूर की नौबत आई। इन घटनाओं से भी विपक्ष ने अपने कुतर्कों से मोदी को घेरने में कोई कमी नहीं की। घरेलू मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती तो मातृ संस्था संघ की ओर से आ रही है। सन 22 के यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के एक बयान से विवाद के बाद संघ पदाधिकारियों द्वारा इशारों इशारों में बार बार निशाने साधे जा रहे है। बीच बीच में विचार विमर्श से विवाद कम हुआ है, मगर दरार अभी भी दिखाई देती है।

घरेलू मुद्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से मोदी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ी है। कोविड़ की वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर होने एवं उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध से खाद्य पदार्थ, खाद, तेल आयात में रुकावट आने से महंगाई बढ़ी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के रूस से व्यापार प्रतिबंध लगा देने से क्रूड ऑयल सप्लाई में कमी आई। ट्रंप यही नहीं रुके उन्होंने भारत पर रूस से व्यापार करने की वजह से अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इससे भारत अमेरिकी ट्रेड डील ट्रेड वार में बदल गई। बाद में ट्रंप ने भारत से अतिरिक्त टैरिफ तो हटा दिया लेकिन सिर्फ अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए जो शर्तें वे हम पर थोपना चाहते थे, वे हमें मंजूर नहीं थी, नतीजन आज तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाने से भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका - इजराइल ईरान के बीच जंग छिड़ जाने से ईरान से आयात होने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित होने तथा रिजर्व्ड कोटे में कमी आने एवं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से महंगाई बढ़ी। विपक्ष के अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति समझने के बावजूद मोदी को जिम्मेदार ठहरा असंतोष फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का एक मौका और मिल गया। यह युद्ध वास्तव में इजरायल और ईरान के बीच होने एवं भारत के दोनों से अच्छे संबंध होने के कारण नीतिगत निर्णयों में संतुलन बनाए रखना कम चुनौती भरा नहीं है। मोदी कठिन परिस्थियों में भी कभी विचलित नहीं होते। लेकिन राममंदिर प्रकरण, नीट पेपर लीक मामला, संघ से विवाद, अमेरिका से ट्रेड डील, रूस यूक्रेन और अमेरिका ईरान युद्ध से आए व्यापार घाटे एवं उससे बिगड़ी आर्थिक परिस्थितियों जैसे तात्कालिक मसलों से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती मोदी के सामने है। मोदी के लिए कुछ कठोर एवं अप्रिय निर्णय लिए बिना इन मुश्किलों एवं चुनौतियों से उबरना आसान नहीं होगा।

सड़क दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं रोकथाम के लिए हो उच्च स्तरीय शोध

अनुसंधान

एलएस हरदेनिया

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इन दिनों हमारे देश व प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। ये घटनाएं क्यों होती हैं इस पर गहन चिन्तन आवश्यक है। इन घटनाओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए संस्थान स्थापित होने चाहिए। ये संस्थान यह जानने का प्रयास करें कि ये घटनाएं क्यों होती हैं। ये संस्थान प्रत्येक सड़क दुर्घटना की विस्तृत जानकारी लें। वाहन की स्पीड क्या थी, ड्राइवर की मानसिक अवस्था क्या थी, क्या वह नशा किए हुए था, सड़क की क्या स्थिति थी, गाड़ी के भीतर क्या सवारी ज्यादा थीं, क्या वह ओवरटेक कर रहा था, गाड़ी में लाईट की क्या स्थिति थी, आदि।

संस्थान में अत्यधिक योग्य शोधकर्ता और विशेषज्ञ रखे जायें। अनुसंधान के जो भी नतीजे निकलें उन पर अमल किया जाए। प्रायः देखा गया है कि देर रात्रि को चलने वाले वाहन ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ड्राइवर की क्षमता से ज्यादा काम करवाना भी खतरनाक होता है। दुर्घटना की खबरों में लिखा जाता है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी। ड्राइवर को ऐसी स्थिति में न रखा जाए जिससे उसे झपकी आए। कुल मिलाकर इस समय सड़क परिवहन के मामले में काफी लापरवाही बरती जाती है। यदि इस क्षेत्र में अनुसंधान किया जाए तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।

इसी तरह इस समय आत्महत्याएं भी बहुत बढ़ रही हैं। विशेषकर युवा और छात्र-छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं। वैसे आत्महत्या का कारण क्या है यह पता लगाना काफी कठिन होता है। कभी-कभी पत्नी, मां, बाप, दोस्त भी नहीं जान पाते कि किसी ने आत्महत्या क्यों की। प्रायः अनजान कारणों से आत्महत्या की जाती है। जैसे मैंने एक छात्र का विवरण पढ़ा उसने बताया कि वह आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था इसी बीच उसके एक दोस्त ने दरवाजा खटखटा दिया और वह आत्महत्या करने से बच गया। आत्महत्या एक अत्यधिक क्रूर कदम है। यदि आत्महत्या की हर घटना का बारीकी से अनुसंधान हो तो हम ऐसे पीड़ितों की जान बचा पायेंगे जो आत्महत्या करना चाहते हैं। इसके लिये भी एक उच्च स्तरीय संस्थान स्थापित किया जाए और जिसमें इस विषय पर अनुसंधान हो कि लोगों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर किस तरह नियंत्रण पाया जाए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सुधीर देशपांडे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

आ मैं तैनूं चा पिलावां...!

पिछले दिनों में गीत बहुत वायरल हुआ था। इतना कि एक बार आपने इसे लाइक कर दिया तो इसके तमाम संस्करण आपके सामने दनादन आते गये। इसी गीत ने बताया कि चाय में बादाम भी डलते हैं। अजी चाय का मामला ही ऐसा है। चाय पैदा कहाँ हुई, किसने पहले पिलाई, किसने किसे फ्री में पिलाई और अब इसके लिए कहाँ कितने पैसे क्षमा करें, कितने रुपए खर्चने पड़ते हैं इसका चर्चा बेमानी है। हाँ यदि किसी ने चाय के लिए भी न पूछा तो तय मानिए बेचारे का यह कृत्य उसे भी वायरल कर देगा कि देखो, इतने दिनों बाद मैं उससे मिला और उसने चाय तक का न पूछा। आलोचना तो बनती है, घर में दूध, शकर, पत्ती, पानी गैस हो न हो, चाय पिलाना तो उसका धर्म है। वैसे आजकल धर्म पर चर्चा सहज ही हो जाती है। हम धर्म की बात करें तो तत्काल विरोध में खड़े हो जाएंगे, धर्म के कारण ही यह देश पिछड़ा है। दूसरे के लिए धर्म है तो राष्ट्र है। अब यदि चाय के बारे में बात करें तो यह पिलाना भी धर्म है और पीना भी धर्म ही है। कुछ भी हो इसको मानने वाले संपूर्ण विश्व में प्रसारित है।

लोग कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ कवि की दृष्टि पहुँच जाती है। एक कहावत और कही जा सकती है- जहाँ भी आदमी जाय, वहाँ मिलेगी चाय। चाय का आलम यह है कि घर आया मेहमान और पेट में छाया तूफान चाय के बगैर जाता ही नहीं। और तो और चाय की हाय इतनी बुरी लगती है कि रास्ते में अनहोनी या काम में असफलता की गारंटी की आशंका भारी हो जाती है। 'बिना कहे चाय लाकर दो तो क्यों तकलीफ़ की' का जुमला और चाय का पूछो तो, 'अरे भाभी, चलते चलते चाय की नाट मत लगाया करो, चलो पिला ही दो। आधा कप ही देना।' वाला कथन हमेशा की तरह जुबान पर रहता ही है। तीसरे न पूछो तो, चाय तक के लिए न पूछा वाला जुमला। आखिर आदमी जाए तो जाए कहाँ। वस्तुतः भारत में चाय का कोई समय नहीं है कहने से अच्छा है कि हम कहें हर समय चाय का समय है। लोग दुनिया भर के बहाने करें कि बहुत चाय हो गई या चाय से एसीडिटी हो जाती है। चाय न पिएँ तो सुस्ती तारी हो जाती है। पर चाय के प्रकारों पर जाते ही ये सारी शिकायतें पतली गली से न जाने कहाँ निकल लेती है। सादी चाय से लेकर, दालचीनी, इलायची, सोंठ, काली मिर्च, गवती चाय, अदरक, पुदीना, नींबू वाली, गुड़ की चाय, मसाले वाली चाय, काली चाय, हरी चाय, मक्खन वाली चाय, मलाई मार के चाय, आपके स्वागत में तैयार है।

भई चाय है तो शिष्टाचार है। नहीं तो इतना भी नहीं सीखे वाला ताना भी है। चाय चिंतन है, चाय चर्चा है, चाय प्रस्ताव है, चाय प्रस्तावना है, चाय समस्या है तो चाय समाधान भी है। चाय है तो साहित्य है, चाय है तो कविता है, चाय से उपस्थिति है। चाय किसी भी आयोजन की सफलता की गारंटी है। चाय पेश करना भी कला है तो बनाना भी कला है। इसे कला के विभिन्न आयाम भी हैं। केवल दूध चाय और शकर का फ्यूजन ही नहीं अपितु इसमें दिल कितना डला है वह भी दिखाई देता है। चाय कुछ के लिए अमृत तुल्य है। कुछ है जो चाय को विष कहने का साहस कर लेते हैं।

चाय बनाने की विधियाँ भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक अलग अलग है। पंचतारा होटलों से लेकर सड़क किनारे के होटलों तक चाय बनाने की विधियां अलग है। इन्हें देखना और भी रोचक है। बड़ी होटलों में जहाँ चाय पानी अलग केतली में, दूध अलग केतली में तो शकर अलग बर्तन में दी जाती है, वहीं सड़क के किनारे होटलों में ये सब एक साथ, समरस होकर हाथ में आते हैं। कुछ भी हो भारत में एक बार खाना न पूछें चलेगा, चाय न पूछेंगे तो आपकी मलामत तय है। तो चाय पीने कब आएँ?

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

क्या बच्चों की सुरक्षा सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी?

आज भारत में लाखों विद्यार्थी अपने घरों से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोटा, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे शहर शिक्षा के बड़े केंद्र बन चुके हैं। अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें इन संस्थानों में भेजते हैं। वे फीस भरते हैं, हॉस्टल का खर्च उठाते हैं और यह भरोसा करते हैं कि जहां उनका बच्चा पढ़ रहा है, वहां उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दुर्भाग्य से यह भरोसा कई बार टूट जाता है। ऐसे हादसे अचानक नहीं होते। इनके पीछे वर्षों की लापरवाही, नियमों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी होती है। जब किसी इमारत में पर्याप्त आपातकालीन निकास नहीं होते, जब बिजली की वायरिंग मानकों के अनुरूप नहीं होती, जब फायर एक्सटिंग्विशर केवल दिखावे के लिए लगाए जाते हैं, जब भवन निर्माण नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, तब किसी भी दिन एक छोटी–सी चिंगारी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है।

लखनऊ में हुए हालिया कोचिंग अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। धुएँ से घिरी इमारतें, चीखते-बिलखते विद्यार्थी, घबराए हुए अभिभावक और राहत-बचाव दलों की भागदौड़–ये दृश्य केवल एक दुर्घटना की तस्वीर नहीं हैं, बल्कि हमारी व्यवस्था की उन कमजोरियों का आईना हैं जिन्हें हम वर्षों से अनदेखा करते आ रहे हैं। हर बार किसी बड़े हादसे के बाद कुछ दिनों तक शोक, संवेदना और आक्रोश दिखाई देता है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा केवल कुछ दिनों की खबर बनकर रह जाएगी? क्या हम तब तक जागेंगे नहीं, जब तक अगली त्रासदी किसी और शहर में, किसी और कोचिंग संस्थान या हॉस्टल में घटित नहीं हो जाती?

आज भारत में लाखों विद्यार्थी अपने घरों से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोटा, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे शहर शिक्षा के बड़े केंद्र बन चुके हैं। अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें इन संस्थानों में भेजते हैं। वे फीस भरते हैं, हॉस्टल का खर्च उठाते हैं और यह भरोसा करते हैं कि जहां उनका बच्चा पढ़ रहा है, वहां उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दुर्भाग्य से यह भरोसा कई बार टूट जाता है।

ऐसे हादसे अचानक नहीं होते। इनके पीछे वर्षों की लापरवाही, नियमों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी होती है। जब किसी इमारत में पर्याप्त आपातकालीन निकास नहीं होते, जब बिजली की वायरिंग मानकों के अनुरूप नहीं होती, जब फायर एक्सटिंग्विशर केवल दिखावे के लिए लगाए जाते हैं, जब भवन निर्माण नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, तब किसी भी दिन एक छोटी-सी चिंगारी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है।

इस घटना के बाद सबसे पहला प्रश्न अभिभावकों को स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने कभी अपने बच्चे के कोचिंग संस्थान, हॉस्टल या पीजी की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक जांच की है? अक्सर हम संस्थान की प्रतिष्ठा, परिणाम और सुविधाओं के बारे में पूछते हैं, लेकिन सुरक्षा संबंधी प्रश्नों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रवृत्ति बदलनी होगी। बच्चे के भविष्य जितना महत्वपूर्ण है, उसका जीवन और सुरक्षा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

अभिभावकों को सबसे पहले आपातकालीन निकास की स्थिति की जांच करनी चाहिए। किसी भी भवन में आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकास जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकता है। कई संस्थानों में आपातकालीन सीढ़ियां या तो बंद रहती हैं या उनमें सामान भरा रहता है। कुछ जगहों पर सुरक्षा द्वारों पर ताले लगे होते हैं। ऐसी स्थिति में भगदड़ और अफरा-तफरी के दौरान बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। यदि किसी भवन में आपातकालीन निकास स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं हैं या उनके उपयोग में कोई बाधा है, तो उसे गंभीर चेतावनी समझना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता है। फायर एक्सटिंग्विशर केवल दीवारों पर टांग देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। उनकी नियमित जांच, रखरखाव और समय-समय पर रिफिलिंग आवश्यक है। अभिभावकों को यह जानने का अधिकार है कि संस्थान में कितने अग्निशमन यंत्र हैं, उनकी वैधता क्या है और क्या स्टाफ को उनके उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। यदि कोई संस्थान इन सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं देता, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर संदेह होना चाहिए। तीसरा मुद्दा फायर एनओसी यानी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र का है। हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि कागजों पर सभी नियम पूरे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग होती है। कई बार निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। इसलिए केवल एनओसी की प्रति देखना पर्याप्त नहीं है। उसकी वैधता, निरीक्षण रिपोर्ट और सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति की भी जांच आवश्यक है। प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि फायर एनओसी केवल कागजी प्रक्रिया न रह जाए, बल्कि वास्तविक सुरक्षा का प्रमाण बने।

इमारत की संरचना भी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई कोचिंग संस्थान संकरी गलियों में स्थित बहुमंजिला इमारतों में संचालित होते हैं। इनमें पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होता, खिड़कियां सीमित होती हैं और भीड़ क्षमता से कहीं अधिक होती है। ऐसी इमारतें दुर्घटना की स्थिति में मौत के जाल में बदल सकती हैं। इसलिए भवन निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा केवल उपकरणों से नहीं आती, बल्कि तैयारी से भी आती है। क्या संस्थान नियमित फायर ड्रिल आयोजित करता है? क्या विद्यार्थियों को

बताया जाता है कि आपातकाल की स्थिति में क्या करना है? क्या स्टाफ को प्राथमिक आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है? इन प्रश्नों के उत्तर अक्सर नकारात्मक होते हैं। जबकि विकसित देशों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में नियमित सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य होता है। भारत में भी यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

यह समस्या केवल कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं है। हॉस्टल, पीजी, छात्रावास और निजी आवासीय व्यवस्थाएं भी अक्सर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती हैं। अनेक स्थानों पर क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को रखा जाता है। संकरी सीढ़ियां, बंद खिड़कियां और खराब विद्युत व्यवस्था जोखिम को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसलिए सुरक्षा का दायरा व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए।

प्रशासन की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्घटना के बाद जांच समिति गठित करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि नियमित निरीक्षण और कठोर निगरानी की व्यवस्था विकसित की जाए। प्रत्येक शहर में कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों का वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। जिन संस्थानों में गंभीर खामियां पाई जाएं, उन्हें सुधार तक संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इसके साथ ही स्थानीय निकायों और अग्निशमन विभाग को तकनीकी संसाधनों और मानवबल से मजबूत बनाना होगा। कई बार दुर्घटना के दौरान फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाती। संकरी गलियां, ट्रैफिक और अपर्याप्त संसाधन राहत कार्यों को प्रभावित करते हैं। यदि हम वास्तव में ऐसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं, तो आपातकालीन सेवाओं को अधिक सक्षम बनाना होगा। समाज और मीडिया की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मीडिया को केवल सनसनीखेज तस्वीरें दिखाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे उन कारणों की गहराई से पड़ताल करनी चाहिए जो ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। वहीं समाज को भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करने से आगे बढ़कर सक्रिय भागीदारी करनी होगी। अभिभावक संगठनों, नागरिक समूहों और सामाजिक संस्थाओं को सुरक्षा मानकों की निगरानी और जागरूकता अभियान में भाग लेना चाहिए।

आज आवश्यकता एक सामूहिक आंदोलन की है। जिस प्रकार स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाए गए, उसी प्रकार शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक अभियान की जरूरत है। प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक छात्र और प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि सुरक्षा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अक्सर हादसों से सीखते नहीं हैं। दिल्ली, सूरत, राजकोट, कोटा और देश के कई अन्य हिस्सों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार जांच हुई, रिपोर्टें बनीं, सिफारिशें आईं और फिर धीरे-धीरे सब कुछ भुला दिया गया। यदि इस बार भी हम केवल शोक व्यक्त करके आगे बढ़ गए, तो यह उन मासूम बच्चों के प्रति अन्याय होगा जिनके सपने और जीवन इन दुर्घटनाओं की भेंट चढ़ जाते हैं।

अंततः यह समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है और केवल अभिभावकों का दायित्व भी नहीं। यह एक साझा उत्तरदायित्व है जिसमें संस्थान, सरकार, समाज, मीडिया और परिवार सभी की भूमिका है। जब तक जवाबदेही की संस्कृति विकसित नहीं होगी, तब तक नियम केवल कागजों में रहेंगे और हादसे दोहराए जाते रहेंगे।

आज आवश्यकता है कि हर अभिभावक अपने बच्चे के संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था की व्यक्तिगत रूप से जांच करे। संचालकों से सवाल पूछे, प्रमाण मांगे और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आवाज उठाए। बच्चों के जीवन से बड़ा कोई समझौता नहीं हो सकता।

लखनऊ का यह अग्निकांड केवल एक शहर की त्रासदी नहीं है। यह पूरे देश के लिए चेतावनी है। यदि हम अब भी नहीं जागे, तो अगली खबर किसी और शहर से आएगी, किसी और परिवार की दुनिया उजड़ जाएगी और हम फिर वही सवाल पूछेंगे-क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी?

समय आ गया है कि इस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, ठोस कार्रवाई से दिया जाए।

सामयिक

लोकेंद्र नामजोशी

लेखक स्तंभकार हैं।

रामभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़

इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर में दान की राशि में से रकम चोरी की खबर से प्रत्येक रामभक्त अपने आप को बहुत आहत, उद्वेलित और दुःखी महसूस कर रहा है। दुःख उसे केवल इस बात का नहीं है कि यह महज एक चोरी की घटना है। बल्कि इस बात का है कि उसकी आस्था उसकी भक्ति के केंद्र रहे स्थान पर ऐसी घटना को इतनी आसानी से कैसे अंजाम दे दिया गया। वह इस बात को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा कि, इतना विश्व प्रसिद्ध मंदिर, इतनी चाक-चौबंद व्यवस्था और सरकारी सुरक्षा का इतना तामझाम होने के बावजूद दान की राशि कैसे चोरी हो गई। वह बहुत उद्वेलित है। उसके मन मे मची इस उथल-पुथल की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिससे वह अपने आप को बहुत असहाय और निराश महसूस कर रहा है।

दरअसल, प्रत्येक रामभक्त की ऐसी निराशा स्वाभाविक रूप से लाजमी है। क्योंकि सभी भक्तों ने इस भव्य मंदिर में रामलला के स्थापित होने की कामना में पांच सो वर्षों की अथक प्रतीक्षा का दंश झेला है। इसलिए सभी भक्तगण इस प्रतीक्षा की समाप्ति के बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण से अपने आप को बहुत पुलकित, उत्साहित और आनंदित महसूस कर रहे थे। क्योंकि उनकी वर्षों की आस, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा उनकी सालों की तपस्या उन सभी के जीते जी फलीभूत हुई थी। अयोध्या में स्थापित इस रामलला की भव्य मूर्ति के दर्शन कर वह अपने आप को धन्य समझ रहे थे। लेकिन जब से अयोध्या के इस राममंदिर में रामभक्तों के द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे दान की राशि में चोरी की खबर सुनी है, वह अंदर से आहत और दुःखी हो गए है।

दरअसल, रामभक्तों के लिए अयोध्या में रामलला की स्थापना का कार्य केवल एक धार्मिक परियोजन नहीं था। बल्कि यह उनकी आस्था, भावनाओं और वर्षों के संघर्ष का प्रतीक था। देश के कोने-कोने से लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार चंदा दान किया था। किसी ने सौ रुपये दिए, किसी ने हजारों और लाखों रुपये का योगदान किया। अनेक परिवारों ने अपनी बचत का हिस्सा समर्पित किया तो कई बच्चों ने अपनी गुल्लक तक मंदिर निर्माण के लिए अर्पित कर दी। यह केवल एक दान की धनराशि नहीं थी, बल्कि यह भगवान श्रीराम के प्रति भक्तों की निष्ठा और विश्वास का प्रमाण था।

ऐसे में जब यह समाचार सामने आया कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर की दानपेटियों से दान की राशि चोरी हो गई, तो स्वाभाविक रूप से देशभर के श्रद्धालु स्तब्ध रह गए। जिस स्थान को करोड़ों लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, वहां ऐसी घटना का होना अनेक प्रश्न खड़े करता है। राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना की चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे लेकर ताने मार रहे हैं और मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग हटकर देखा जाए तो सबसे बड़ी चोट भक्तों की भावनाओं पर पहुंची है।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि, देश के अनेकों छोटे-बड़े मंदिरों में दानपेटियां वर्षों से रखी हैं। जहां पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसी जगहों से भी इस प्रकार धनराशि चोरी होने की घटनाए सुनने को नहीं मिलती हैं। ऐसे में देश के सबसे चर्चित और सुरक्षित माने जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक में ऐसी घटना होना चिंता का विषय है।

दरअसल, यह घटना केवल एक चोरी नहीं, बल्कि उस व्यापक समस्या की ओर भी संकेत करती है जो आज समाज के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देती है। भ्रष्टाचार और अनैतिकता किसी दीमक की तरह व्यवस्था को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। जब व्यक्ति की लालच और धनलोलुपता इस सीमा तक पहुंच जाए कि वह धार्मिक स्थल में रखी श्रद्धालुओं की भेंट पर भी हाथ डालने से न हिचके, तब यह केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का भी प्रश्न बन जाता है। यह भ्रष्टाचार की ही भूख है जो करोड़ों लोगों की आस्था पर भारी पड़ रही है।

हालांकि, इसे हम केवल भ्रष्टाचार या लालच का मामला कहकर ही पल्ला नहीं झाड़ सकते। कारण यह सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला भी नजर आ रहा है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई। इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था में यह लापरवाही क्यों बरती गई? हमारे देश के कई प्रमुख मंदिरों में दान प्रबंधन के लिए अत्यंत सख्त व्यवस्था अपनाई जाती है। दानपेटियों को विशेष सील के साथ सुरक्षित रखा जाता है। उन्हें खोलने के समय प्रशासनिक अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। इन उपायों का उद्देश्य केवल धन की सुरक्षा नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखना भी है। दोषियों के विरुद्ध त्वरित और कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है। हालांकि, इस मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है और जांच प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही सामने आएंगे। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम ने व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी अनेक सवालों को जन्म दिया है।

अंततः प्रश्न केवल चोरी हुई राशि का नहीं है। वास्तविक मुद्दा उस विश्वास का है जिसे करोड़ों भक्तों ने भगवान श्रीराम के मंदिर से जोड़ा है। इसलिए यह घटना एक गंभीर आत्ममंथन का अवसर है। अब यह जांच का विषय है कि यह मामला भ्रष्टाचार की असीमित भूख का परिणाम था या सुरक्षा व्यवस्था में हुई गंभीर चूक का। किंतु जो भी कारण हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भविष्य में किसी भी श्रद्धालु की आस्था को इस प्रकार ठेस न पहुंचे। यही श्रीराम मंदिर की गरिमा और करोड़ों भक्तों के विश्वास की सच्ची रक्षा होगी। ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार रामभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके।

कोचिंग सेंटर अग्निकांड

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

मासूमों की मौत पर कब तक खामोश रहेगा 'सिस्टम'?

लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में 15 मासूम जिंदगियों का बुझ जाना केवल एक दुखद घटना नहीं है बल्कि यह उस सड़ी-गली व्यवस्था का आईना है, जो हर बार इंसानी जानों की कीमत पर अपनी लापरवाही को ढ़कने की कोशिश करती है। दम घुटने से बाथरूम में छिपे छात्रों की मौत, छज्जों से कूदकर जान बचाने की कोशिश करते युवा, बंद दरवाजों में कैद उम्मीदें, ये दृश्य किसी दुर्घटना के नहीं बल्कि एक सुनियोजित विफलता के हैं। सवाल यह है कि क्या यह महज हादसा है या 15 निर्दोष विद्यार्थियों की सामूहिक हत्या? लखनऊ की इस घटना को यदि अलग-थलग देखा जाए तो हम सच्चाई से आंखें मूंद लेंगे। यह घटना उसी श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसमें कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत हुई थी और उससे पहले भी दिल्ली के मुंडका, करोल बाग, अनाज मंडी, उपहार सिनेमा तथा देश के विभिन्न हिस्सों में न जाने कितने अग्निकांडों में सैंकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। हर बार कहानी एक जैसी होती है, अवैध निर्माण, फायर एनओसी का अभाव, बंद निकास द्वार या एक ही प्रवेश और निकास द्वार, भीड़भाड़ वाली इमारतें और प्रशासन की आंखों पर बंधी मिलीभगत की पट्टी।

लखनऊ अग्निकांड के शुरुआती तथ्यों ने एक बार फिर वही सच्चाई उजागर की है। जिस इमारत में आग लगी, उसका नक्शा तो पास था लेकिन निर्माण उसके विपरीत किया गया। सेटबैक तक को कवर कर लिया गया। नीचे पेट शॉप और गेमिंग जोन, ऊपर कोचिंग और लाइब्रेरी यानी एक ही इमारत में बिना सुरक्षा मानकों के कई तरह की गतिविधियां। सबसे गंभीर तथ्य यह कि कोचिंग का दरवाजा बंद था, जिससे छात्र बाहर नहीं निकल सके। यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक उपेक्षा है। यह प्रश्न बार-बार उठता है कि आखिर ऐसी इमारतें बन कैसे जाती हैं? क्या प्रशासन को पता नहीं होता? क्या बिजली विभाग, नगर निगम, फायर विभाग, पुलिस, इनमें से किसी को भी जानकारी नहीं होती? सच यह है कि सबको जानकारी होती है लेकिन व्यवस्था की मिलीभगत और भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि नियम केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं।

जब कोई अवैध इमारत बनती है तो उसकी नींव खोदी जाती है, दीवारें खड़ी होती हैं, लेंटर डलता है। उस दौरान स्थानीय नगर निगम, विकास प्राधिकरण और पुलिस के अफसर कहां सो रहे होते हैं? क्या उनकी आंखों के सामने यह निर्माण नहीं होता? जिस इमारत के पास फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट (फायर एनओसी) नहीं है, उसे बिजली विभाग कमर्शियल कनेक्शन कैसे दे देता है? जल संस्थान पानी का कनेक्शन कैसे जारी करता है? गंभीर प्रश्न यह है कि एक ही संकरी इमारत में नीचे गेमिंग जोन और ऊपर सैंकड़ों बच्चों की कोचिंग चलाने की अनुमति किस कानून के तहत दी गई? क्या प्रशासन को नहीं पता कि ऐसी जगहों पर पैर रखने की जगह नहीं होती? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसे किसी भी मामले में बड़े अधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरती? सस्पेंशन हमेशा छोटे कर्मचारियों का ही क्यों होता है? उस क्षेत्र के तत्कालीन अवैध निर्माण प्रभारी, जोनल कमिश्नर या मुख्य अग्निशमन अधिकारी को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जाता?

भारत के शहरों में निर्माण की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती। पहले जमीन का उपयोग बदलता है, फिर नक्शा पास होता है, फिर धीरे-धीरे निर्माण होता है, बिजली-पानी के कनेक्शन मिलते हैं और अंततः व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दर्जनों अधिकारी और विभाग शामिल होते हैं। ऐसे में यह कहना कि प्रशासन अनजान था, वास्तविकता से मुंह चुराना है। सच्चाई यह है कि यह सब कुछ प्रशासन और बिल्डर-व्यापारियों की सांठगांठ से होता है। दिल्ली के मालवीय नगर की घटना में भी यही सामने आया था कि छह कमरों की अनुमति के बावजूद 25 से अधिक कमरे बनाए गए थे। केवल एक निकास मार्ग था और वह भी प्रभावी नहीं था। बेसमेंट का गेट बंद था। आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल सके थे। यह वही कहानी है, जो 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में देखी गई थी, जहां बंद निकास द्वारों के कारण 59 लोगों की जान गई थी। इतिहास गवाह है कि हर बड़े अग्निकांड के बाद सख्त नियमों की बात होती है, जांच आयोग बनते हैं, मुआवजे घोषित होते हैं और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है लेकिन क्या कभी किसी बड़े अधिकारी को सजा मिली? क्या कभी ऐसी कार्रवाई हुई, जिससे भविष्य में कोई नियमों की अनदेखी करने की हिम्मत न करे? जवाब स्पष्ट है, नहीं।

लखनऊ और दिल्ली की घटनाएं साफतौर पर बताती हैं कि हमारी व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक है, सक्रिय नहीं। जब तक हादसा नहीं होता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती और जब हादसा हो जाता है, तब केवल औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। यह एक ऐसा चक्र बन चुका है, जिसमें हर बार आम आदमी की जान जाती है और व्यवस्था बच निकलती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज शहरों में हजारों ऐसी इमारतें मौजूद हैं, जो किसी भी समय मौत का जाल बन सकती हैं। संकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें, बेसमेंट में अवैध फैक्ट्रियां, बिना वेंटिलेशन के कोचिंग सेंटर, बंद खिड़कियां, लोहे की ग्रिलें, और केवल एक प्रवेश-निकास द्वार, ये सब मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म देने के लिए पर्याप्त हैं, जो किसी भी दिन सामने आ सकती है। फायर सेफ्टी के उपकरण अक्सर केवल दिखावे के लिए लगाए जाते हैं। कई जगह तो ये उपकरण काम ही नहीं करते। आपातकालीन निकास कागजों में तो होते हैं लेकिन वास्तविकता में बंद या अवरुद्ध पाए जाते हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां अक्सर संकरी गलियों के कारण घटनास्थल तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे में जब आग लगती है तो वह केवल इमारत को नहीं बल्कि इंसानी उम्मीदों को भी जलाकर राख कर देती है। लखनऊ अग्निकांड में छात्रों का बाथरूम में छिपकर दम घुटने से मर जाना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। यदि पर्याप्त निकास द्वार होते, यदि दरवाजे खुले होते, यदि फायर सेफ्टी के उपकरण सही तरीके से काम कर रहे होते तो शायद ये 15 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। सवाल यह है कि इस स्थिति का समाधान क्या है? क्या हर बार केवल शोक व्यक्त करना और मुआवजा देना ही पर्याप्त है? क्या हम तब तक इंतजार करेंगे, जब तक अगली आग किसी और शहर में, किसी और इमारत में, किसी और परिवार को उजाड़ न दे? समाधान स्पष्ट है लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। सबसे पहले सभी व्यावसायिक और बहुमंजिला इमारतों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए। फायर एनओसी की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए। अवैध निर्माण पर केवल जुर्माना नहीं बल्कि तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। केवल छोटे अधिकारियों को निलंबित कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों और संबंधित विभागों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब तक कोई वास्तविक सुधार संभव नहीं है। ऐसे मामलों में गैर-इरादतन हत्या नहीं बल्कि कठोर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिएं। लखनऊ का अग्निकांड एक चेतावनी है। यह केवल 15 लोगों की मौत की कहानी नहीं है बल्कि उस व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है, जो हर बार अपने नागरिकों को असुरक्षित छोड़ देती है। यदि इस बार भी हम नहीं जागे तो यह निश्चित है कि अगला अग्निकांड केवल समय की बात है। तब फिर वही सवाल गूंजेगा कि क्या यह हादसा था या हत्याकांड? और तब शायद जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए केवल घड़ियाली आंसू बहाना बंद करना होगा। आज जरूरत आत्ममंथन की और इस सड़े हुए सिस्टम को पूरी तरह बदलने की है। यदि अब भी हम चुप रहे तो कल उस जलती हुई इमारत की खिड़की से कूदने वाला बच्चा या दम तोड़ने वाला छात्र हमारे अपने घर का भी हो सकता है।

धार में बुधवार को झमाझम बारिश

ग्यारसपुर, विदिशा में बिजली कर्मियों से मारपीट एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने पर आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

भोपाल/विदिशा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विदिशा वृत्त के अटारी खेजड़ा पंप फीडर की 11 केवी विद्युत लाइन में अवरोध उत्पन्न कर शासकीय कार्य में बाधा डालने तथा विद्युत कार्मिकों से अभद्रता एवं मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी के विरुद्ध थाना ग्यारसपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ग्यारसपुर विद्युत वितरण केंद्र के सहायक प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि ग्राम मढीपुर के किसानों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि मालम सिंह उर्फ नाना राजपूत, पिता रतन सिंह राजपूत, निवासी ग्राम मढीपुर द्वारा उसके खेत से होकर गुजरने वाली 11 केवी अटारी खेजड़ा पंप लाइन को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है, जिससे पिछले लगभग चार माह से विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने से उनकी फसलें एवं सब्जियां नुकसान झेल रही हैं।

किसानों की शिकायत के आधार पर 23 जून 2026 को सहायक प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत, प्रबंधक श्री गोपाल मसराम, लाइन परिचालक श्री अनिल घोसी एवं विद्युत सहायक श्री अभिजीत घोसी द्वारा मौके का निरीक्षण करने तथा जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई। आरोपी के द्वारा विद्युत लाइन के तीनों तार रस्सी से बांधकर फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी, जिसके कारण संबंधित क्षेत्र के किसानों को विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी। स्थिति का संज्ञान लेते हुए सहायक प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत ने कर्मचारियों को विद्युत लाइन से फॉल्ट हटाकर आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। इसी दौरान आरोपी मालम सिंह ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया। कंपनी द्वारा घटना की जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को देने के उपरांत थाना ग्यारसपुर द्वारा आरोपी मालम सिंह उर्फ नाना, पिता रतन सिंह राजपूत, निवासी ग्राम मढीपुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 132, 296(b), 281, 324(2), 351(3) तथा विद्युत अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत चोरी की रोकथाम एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। कंपनी का सतर्कता विभाग एवं क्षेत्रीय अधिकारी विद्युत चोरी, लाइन क्षति तथा विद्युत तंत्र में अवरोध उत्पन्न करने वाले मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार या शासकीय कार्य में बाधा डालने की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज कराकर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नरेंद्र मोदी विचार मंच मुख्य शाखा के प्रदेश मीडिया प्रभारी कैलाश मुकाती सम्मानित

धार। जन परिषद मनावर चेप्टर अध्यक्ष व नरेंद्र मोदी विचार मंच मुख्य शाखा के प्रदेश मीडिया प्रभारी कैलाश मुकाती वीआईपी मनावर का नरेंद्र मोदी विचार मंच मुख्य शाखा मध्यप्रदेश के 23वें स्थापना दिवस पर सम्मान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य,प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार सांखला, प्रदेश प्रभारी महेशचंद्र माहेश्वरी व अन्य पदाधिकारियों द्वारा स्थापना दिवस के गरिमामय समारोह में कैलाश मुकाती का सम्मान किया।

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना का कलेक्टर मीना ने किया औचक निरीक्षण, निर्माण कार्यों में गति लाने के दिए निर्देश

धार। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आज कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माणाधीन बांध स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की वर्तमान प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों व निर्माण एजेंसी मेसर्स ए. एन.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्य की गति में और अधिक तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने परियोजना के तहत प्रस्तावित नहर निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया

को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने को कहा, ताकि क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ समय पर मिल सके। इस दौरान संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए 304.44 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें बांध निर्माण की अनुबंधित लागत 99.86 करोड़ रुपये है। वर्तमान में परियोजना के भौतिक कार्यों में अच्छी प्रगति देखी जा रही है, जिसके अंतर्गत कुल 18,01,530 घन मीटर अर्थवर्क में से 16,64,130 घन मीटर और 1,21,509 घन मीटर कांक्रीट कार्य में से 1,12,200 घन मीटर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 590 मीटर लंबी इस बांध संरचना के पूर्ण होने पर धार जिले की धरमपुरी तहसील के 42 आदिवासी बाहुल्य गांवों के कृषकों को 8750 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल की महत्वपूर्ण सुविधा प्राप्त होगी।

जनसुनवाई में 17 शिकायतें, दिव्यांग राजेश के पास स्वयं पहुंची एसडीएम सुश्री प्रियंका भल्लावी

सोहागपुर। कभी-कभी शासकीय कार्यालयों में ऐसे नजारे भी देखने को मिल जाते हैं। जो सभी के लिए अनुकरणीय संवेदनशीलता मिशाल कायम हो जाती है। ऐसी ही वाकिया आज जनपद पंचायत कार्यालय में जनता-जनार्दन को देखने को मिला। जिसमें जनसुनवाई के दौरान राजेश कुमार पिता करन सिंह, उम्र 25 वर्ष, द्वारा दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक की दिव्यांगता को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम सुश्री प्रियंका भल्लावी स्वयं अपने स्थान से उठकर आवेदक के पास पहुंचीं। दिव्यांग से चर्चा कर उनकी समस्या की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके उपरांत जनपद पंचायत के अधिकारियों को आवेदन पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। निर्देशों के परिपालन में जनपद पंचायत के कर्मचारियों ने आवेदक का आवेदन तत्काल पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। आवेदक एवं उनके परिजनों ने प्रशासन की संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया है। आज की जनसुनवाई में 17 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिसमें नगर परिषद सोहागपुर, 05 जनपद पंचायत सोहागपुर 01,खाद्य विभाग सोहागपुर 02 तहसील कार्यालय सोहागपुर 03 ऊर्जा विभाग 03 एसडीएम कार्यालय सोहागपुर 02 शिकायतें एवं पुलिस विभाग सोहागपुर ङ्क 01 शिकायतें प्राप्त की गई है। जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री प्रियंका भल्लावी, तहसीलदार आरएस झरबड़े, नगरपालिका अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा सहित समस्त खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा : दीपक वोहरा

बैतूल के पूर्व सांसद स्व. विजय खंडेलवाल सम्मान से गढ़ाकोटा के मनोज तिवारी हुए सम्मानित

बैतूल। अग्रणी सामाजिक संस्था जन परिषद के 37वें वार्षिक समारोह का आयोजन रवीन्द्र भवन, भोपाल में किया गया। इस समारोह में भारत के पूर्व राजदूत एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अग्रणी ज्ञाता दीपक वोहरा, एसीएस अनुपम राजन तथा एयर मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जन परिषद अध्यक्ष एवं मप्र. के पूर्व डीजीपी एन.के. त्रिपाठी ने संस्था की 37 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों और भावी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए की। उन्होंने कहा कि जन परिषद समाज, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम का वार्षिक प्रतिवेदन महेंद्र जोशी ने प्रस्तुत किया। इसमें संस्था की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों, सामाजिक अभियानों, पर्यावरण संरक्षण, जनजागरण तथा सेवा परियोजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन संयोजक रामजी श्रीवास्तव ने तथा अंत में आभार प्रदर्शन, अजय श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त कर किया। कार्यक्रम में जन परिषद के संरक्षक व बैतूल के वरिष्ठ समाजसेवी अरुण किलेदार, जन परिषद के उपाध्यक्ष

मोहन अग्रवाल, जनपरिषद प्रांतीय सचिव वरिष्ठ पत्रकार केपी अग्निहोत्री, जनपरिषद मीडिया प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार संजय द्विवेदी, नर्मदापुरम के पत्रकार ऋषिकुमार त्रिपाठी, नव्या शर्मा, सुरेखा गायकवाड़ सहित देशभर के जन परिषद से जुड़े पदाधिकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त हस्तियां मौजूद रही।

पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा : दीपक वोहरा- कार्यक्रम को सम्बोधित करते मुख्य अतिथि दीपक वोहरा ने कहा कि जन परिषद की 37 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उसके सेवा कार्यों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पहचान को देखते हुए यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियां जन परिषद के रचनात्मक गीतों को गुनगुनाएंगी। उन्होंने कहा कि वे इन दिनों अत्यंत व्यस्त थे और भोपाल आने की स्थिति में भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने जन परिषद के इतिहास, उपलब्धियों और कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा भोपाल के अपने मित्रों से संस्था के संबंध में चर्चा की, तो सभी ने जन परिषद की प्रशंसा की कि वे स्वयं को इस कार्यक्रम में आने से रोक नहीं सके। उन्होंने आचार्य चाणक्य के छह सूत्रों को सरल व प्रेरक ढंग से प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की ओर नहीं देख रहा है, बल्कि पूरा विश्व आशा और विश्वास की दृष्टि से भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने लोगो से आग्रह किया कि वे इन सूत्रों को अपने घरों तक पहुंचाएँ और अपने बच्चों को भी इसके बारे में अवश्य बताएं, ताकि उनमें संस्कार, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित हो। इस मौके पर एसीएस अनुपम राजन ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के विकास में जनभागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया है, वह सभी के लिए अनुकरणीय है। एयर मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव ने युवाओं को संबोधित करते कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और समर्पण अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का संदेश दिया।

प्रसिद्ध हस्तियों के नाम से हुए बुद्धिजीवी सम्मानित- समारोह में एंबेसडर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से पूर्व राजदूत दीपक वोहरा (नई दिल्ली) को सम्मानित किया गया। एक्सीलेंट गार्जियन ऑफ द हार्ट सम्मान से डॉ. सुब्रतो मंडल को सम्मानित किया गया।

नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की नियुक्ति

सोहागपुर। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडे ने सोहागपुर नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। जिसमें पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल की नियुक्ति हो चुकी थी। वर्तमान में उपाध्यक्ष धर्मदास बैलवशी, देवान्शु शर्मा, आरिफ खान, कोषाध्यक्ष भास्कर मांझी, महासचिव मोहन कहार, कार्तिक शर्मा, जयभानु सिंह चंदेल,इलियाना खान,आकाश चौरसिया,आयुष पालीवाल, सचिव ओपी पटेल,शरद सराठे,प्रखर शर्मा, अल्फाफ खान, अंकित पटेल,दीपक मंडल, आशीष मालवीय, योगेन्द्र कपाड़िया, मीडिया प्रभारी अनंत तिवारी एवं सोशल मीडिया प्रभारी कमलेश मालवीय प्रमुख हैं। समस्त नवनियुक्त पदाधिकारियों को कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं स्नेहियो ने बधाई दी हैं।

किसान,डीजल,खाद के लिए परेशान हैं मैं कैसे मनाऊं जन्म-दिन : ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष

सोहागपुर। कांग्रेस ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर ने अपना जन्मदिन मनाने से अपने कांग्रेसी साथियों से मनाकर दिया है। सुधीर ठाकुर ने इस प्रतिनिधि को बताया कि मैं विपक्ष के जिम्मेदार पद पर कार्यरत हूं। वर्तमान में किसान डीजल के लिए परेशान हैं ,उसे अपना समय खेती के लिए देना चाहिए। लेकिन वह पेट्रोल पंप की लाइन में लगा हुआ है। किसानों को गेहूं आदि के लिए खाद पदार्थ मिलना दूभर हो गया है। छात्र अपने उज्जवल भविष्य के चिंतित है। काफी किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं हुआ है। आमजन के साथ कांग्रेस जनों को शासन की व्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे वातावरण में मेरा फर्ज है कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊं। मैंने अपने साथियों से जन्मोत्सव कार्यक्रम निरस्त करने का आग्रह किया है। हम उत्सव न मना कर जनता के लिए शासन की कुव्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष करें । यही मेरा जन्मदिन का उपहार है। यही विपक्ष का धर्म है।

उज्जैन में भी सिंहस्थ के कामों के चलते चुनौती बनेगा मानसून

भोपाल में खुदी सड़कें, जलभराव का खतरा

भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर (नप्र)। मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन एमपी के शहरों की तैयारियां अब भी अधूरी हैं। भोपाल में मेट्रो, फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर और चौड़ीकरण की वजह से सड़कें खुदी पड़ी हैं, तो दूसरी तरफ हर साल जलभराव से जूझने वाले इलाके के लोग फिर चिंता में है। साल बदले, लेकिन इलाकों के हालात नहीं।

यही हाल इंदौर, ग्वालियर-जबलपुर के भी है। मेट्रो की वजह से इंदौर में सड़कें खुदी हुई हैं। उज्जैन में सिंहस्थ के काम चल रहे हैं। चाहे इंदौर रोड हो या, मक्सी, आगर-मालवा, बड़नगर रोड। बीच शहर में भी काम चल रहे हैं। बारिश में काम की रफ्तार धीमी होगी, पर मुसीबतें बढ़ जाएगी। ये निर्माण कार्य मानसून में हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। चार महीने पहले इंदौर में एक बाइक सवार की ऐसे ही एक गड्ढे में गिरकर मौत हो चुकी है। भोपाल में ऑरेंज लाइन के दूसरे रूट- सुभाषनगर से करोंद के बीच 10 किमी में काम चल रहा है। जवाहर चौक भदभदा तक भी यही स्थिति है। भोपाल स्टेशन के बाहर अंडरग्राउंड तो सिंधी कॉलोनी, करोंद, आरिफ नगर समेत पुराने शहर से पिलर खड़े हैं। इससे सड़क की चौड़ाई आधी हो गई है। विधायक आतिफ अकील ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। फिर भी सुधार नहीं हुआ है। इससे बारिश में दिक्कतें बढ़ जाएंगी।

यही हाल मेट्रो की ब्लू लाइन- भदभदा से रत्नागिरी तक के है। न्यू मार्केट से भदभदा तक सड़क छोटी हो गई है। वहीं, रायसेन रोड पर भी ऐसे ही हाल है। हर रोज शाम को जाम लगता है। इससे करोंद, मालीखेड़ी, विदिशा रोड, अयोध्या बायपास समेत कई इलाकों में जाने वाले लोग घंटों तक फंसते हैं।

10 लेन की वजह से अयोध्या बायपास खुदा- भोपाल के अयोध्या बायपास को 10 लेन बनाने का 836 करोड़ का प्रोजेक्ट है। रत्नागिरि से आसाराम तिराहे तक काम चल रहा है। 16 किमी लंबी दस लेन सड़क पर 8 से ज्यादा ब्रिज भी बन रहे हैं। इस वजह से खुदाई की गई है। जगह-जगह से रास्तें डायवर्ट है। रात में दिक्कतें ज्यादा हैं, क्योंकि रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है।

उज्जैन : सिंहस्थ के कामों के बीच मानसून बना चुनौती, कई ब्लैक स्पॉट

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में करीब 13 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें सड़क चौड़ीकरण, ब्रिज, टनल, एलिवेटेड कॉरिडोर, रोप-वे, शॉपिंग मॉल, नगर निगम पार्किंग, महाकाल मंदिर विस्तार और मेडिसिटी परियोजना शामिल हैं। ऐसे में मानसून के दौरान निर्माणाधीन स्थलों पर आम लोगों की परेशानी और हादसों का खतरा बढ़ गया है।

पुस्तक बैंक एक सराहनीय पहल

भोपाल। विद्या वीचारी तां पर उपकारी, अर्थात्, जो ज्ञान को समझकर जीवन में अपनाता है, वही दूसरों के लिए उपकारी बनता है।

यह पंक्ति गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी, गुरुद्वारा गुरू नानक दरबार में संचालित शिक्षा सांझ के उद्देश्य को सार्थक रूप से व्यक्त करती है। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग समाज की सेवा और मानवता के कल्याण में निहित है।

गुरुद्वारे में संचालित पुस्तक बैंक एक सराहनीय पहल है, जो शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज सेवा की भावना को मजबूत करने का कार्य करता है। सिख धर्म के सेवा और परोपकार के सिद्धांतों से प्रेरित यह पुस्तक बैंक जरूरतमंद विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें तथा अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। शिक्षा सांझ की शुरुआत 2022 में गुरुजी की कृपा से हुई। आज इसमें 2000 से ज्यादा पुस्तके और सैकड़ों मेंबर्स हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं।

इस पुस्तक बैंक का लाभ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को मिलता है। वे शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकें प्राप्त करते हैं और उपयोग के बाद उन्हें वापस जमा कर देते हैं, जिससे अन्य विद्यार्थी भी उनका लाभ उठा सकें। इससे छात्रों और उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होता है तथा पुस्तकों के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

गुरुद्वारे के सेवादार पुस्तक दान एकत्रित करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुँचाते हैं। यह पहल शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ समाज में सहयोग और साझेदारी की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। गुरुद्वारे का शिक्षा सांझ समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह न केवल विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि उन्हें उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है।

संक्षिप्त समाचार

हम्माल एवं मजदूरों के मध्य नशा मुक्ति प्रभात वार्ता का हुआ आयोजन

हरदा (निप्र)। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हरदा द्वारा कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में 17 से 26 जून तक नशा मुक्ति सप्ताह के तहत जिले में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को हरदा शहर के बीच विभिन्न चौकों एवं मार्गों पर जाकर विभागीय मास्टर ट्रेनरों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरा लीगल वालंटियर श्रीमती सुरेंद्र कौर के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्परिणामों से हम्माल एवं मजदूरो को अवगत कराया गया। इस दौरान नशे से कैसे खुद को और खुद के परिवार को नशे से बचाव के लिए उपाय भी बताएं गये। इस अवसर पर उपस्थित जनों को नशा मुक्ति शपथ भी दिलाई गई। उपसंचालक श्री कमलेश सिंह ने बताया कि जिले में विभिन्न विभागों की सहभागिता अनुरूप 26 जून तक नशा मुक्ति संबंधी जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जावेगी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बनापुरा के नवनिर्मित पार्क में हुआ वृक्षारोपण

नर्मदापुरम (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा द्वारा बनापुरा क्षेत्र के नवनिर्मित पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के माध्यम से योग द्वारा स्वस्थ जीवन और वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री रितेश जैन, अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) श्री विजय राय, तहसीलदार श्री नितिन झोड़ एवं थाना प्रभारी श्री सुधाकर बारस्कर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने पार्क परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि जिस प्रकार योग शरीर को स्वस्थ और सशक्त बनाता है, उसी प्रकार वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने का माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान योग और प्रकृति के बीच गहरे संबंध पर भी प्रकाश डाला गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्री रितेश जैन ने कहा कि स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। एसडीएम श्री विजय राय सहित अन्य अधिकारियों ने भी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जनसहभागिता को आवश्यक बताया। उपस्थित सभी लोगों ने पौधों की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के डॉ सोनवणे ने दिए निर्देश

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति एवं एनकार्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम तथा नशा मुक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध माइनिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध खनन के मामलों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खनिज निरीक्षकों को फील्ड में सक्रिय रहकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में खनिज एवं पुलिस विभाग के समन्वय से नियमित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात आयोजित एनकार्ड समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ सोनवणे ने नशा मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग को नशा मुक्ति के संबंध में सेमिनार, निबंध प्रतियोगिता तथा जनजागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। खेल विभाग को भी युवाओं में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने कहा कि विद्यालय परिसरों से निर्धारित दूरी के भीतर पान गुमटियों के संचालन पर प्रतिबंध संबंधी निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए।

■ राशन मित्र पोर्टल पर मृत हितग्राहियों के नाम विलोपित कर जोड़ें नए पात्र हितग्राहियों के नाम

मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबल के लंबित आवेदनों का शीघ्र करें निराकरण : कलेक्टर

- वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों के संपरिवर्तन एवं वनाधिकार पट्टों के फौती नामांतरण में तेजी लाने के निर्देश
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों के पंजीयन के कलेक्टर ने दिए निर्देश
- समान नागरिक संहिता एवं ज्ञान भारतम अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
- कलेक्टर की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के समय-सीमा वाले प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबल के अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ मिलना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। कलेक्टर ने कहा कि यह योजना राज्य शासन की महत्वपूर्ण जनहितैषी योजना है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनका त्वरित निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की भी समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक श्रमिकों को योजना से जोड़ने तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन के लिए किसान पंजीयन के सत्यापन कार्य तथा जिले में खाद की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मूंग उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन का सत्यापन निर्धारित समय-सीमा में पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ किया जाए, ताकि पात्र किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने कहा कि जिले में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के माध्यम से खाद वितरण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कृषि कार्यों के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने अधिकारियों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में आमजन से अधिक से अधिक सुझाव प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

एडीबी विशेषज्ञों ने बुधनी टॉय विलेज परियोजना का किया निरीक्षण

प्रगति का लिया जायजा

सीहोर (निप्र)। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (एमपीयूडीसी) की परियोजना क्रियान्वयन इकाई भोपाल अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के विशेषज्ञ सदस्य श्री विवेक विशाल, सुश्री रुपोस्रोता कहाली एवं श्री कार्लिटो द्वारा बुधनी एकीकृत विकास परियोजना के तहत निर्माणाधीन टॉय विलेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञ दल ने परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा विभिन्न अवसंरचनात्मक घटकों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना के क्रियान्वयन, गुणवत्ता मानकों एवं निर्धारित समयसीमा के अनुरूप हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुझाव दिए। विशेषज्ञों ने परियोजना को क्षेत्रीय पर्यटन संवर्धन, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की विकास परियोजनाएँ स्थानीय स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति प्रदान करती हैं। उल्लेखनीय है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा प्रदेश में विभिन्न महत्वाकांक्षी अधोसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य शहरी सुविधाओं का विस्तार एवं समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

पशुपालन में रचा सफलता का नया अध्याय, एक गाय से खड़ा किया आधुनिक डेयरी फार्म

विदिशा (निप्र)। ग्राम पीपलखेड़ा के युवा पशुपालक श्री राजेश धाकड़ ने अपनी मेहनत, लगन और वैज्ञानिक सोच के बल पर यह साबित कर दिया है कि सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते। लगभग दस वर्ष पूर्व केवल एक गाय से पशुपालन की शुरुआत करने वाले राजेश आज 15 उच्च नस्ल की गायों के सफल डेयरी फार्म के संचालक हैं और प्रतिमाह लाखों रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। विदिशा जिले के ग्राम पीपलखेड़ा निवासी श्री राजेश धाकड़ ने दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। प्रारंभिक दौर में उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उनके भीतर आत्मनिर्भर बनने और कुछ नया करने का जज़्बा था। इसी संकल्प के साथ उन्होंने एक गाय से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार सीखने व आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा।

राजेश धाकड़ नियमित रूप से पशुपालन प्रशिक्षण

शिविरों में भाग लेते रहे। इन प्रशिक्षणों से उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन करने की प्रेरणा और तकनीकी जानकारी मिली। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए मार्गदर्शन ने उनके ज्ञान और आत्मविश्वास को नई दिशा दी। उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया।

कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग कर उन्होंने अपनी देशी गायों से उन्नत ॥स्र नस्ल की 15 गायें और एक बछड़ी तैयार की। पशुओं के बेहतर पोषण के लिए वे गेहूं, मक्का, चना, सोयाबीन, सरसों और संतुलित पशु आहार का उपयोग करते हैं। साथ ही वर्षभर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बरसीम, नेपियर और मख्खन घास का उत्पादन भी स्वयं करते हैं। इस वैज्ञानिक प्रबंधन का परिणाम यह हुआ कि उनके डेयरी फार्म में दूध उत्पादन लगातार बढ़ता गया।

वर्तमान में उनके फार्म से प्रतिदिन लगभग 130 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। उन्हें दूध का औसत मूल्य 35 से 38 रुपये प्रति लीटर प्राप्त होता है। डेयरी व्यवसाय को और अधिक संगठित रूप देने के लिए उन्होंने स्वयं की बीएमसी (बल्क मिल्क कूलर) भी स्थापित की है। इसके माध्यम से वे आसपास के पशुपालकों से दूध खरीदकर दुग्ध संघ एवं बाजार में विक्रय करते हैं। इस अतिरिक्त गतिविधि से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आज उनकी मासिक औसत आय लगभग डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। राजेश धाकड़ का सपना अपने डेयरी फार्म को विकसित कर 50 गायों का आधुनिक डेयरी केंद्र स्थापित करना है।

सड़क सुरक्षा, वन अतिक्रमण और जघन्य अपराधों की समीक्षा, कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने दिए सख्त निर्देश

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति एवं वन विभाग की जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा, वन भूमि अतिक्रमण और जघन्य अपराधों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील ब्लैक स्पॉट्स का पुलिस और संबंधित सड़क विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स पर आवश्यक साइनेज, रंबल स्ट्रिप्स सहित अन्य सुरक्षा उपाय तत्काल किए जाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने विगत वर्षों में हुई बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा कर ऐसे स्थलों पर विशेष सुरक्षा कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बैतूल में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करने के निर्देश भी एसडीएम को दिए।

ताकि ट्रांसपोर्ट नगर विकसित होने से भारी वाहनों की शहर के भीतर आवाजाही कम होगी, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी। ट्रकों एवं अन्य मालवाहक वाहनों के लिए पृथक पार्किंग और संचालन व्यवस्था होने से शहर में जाम एवं सड़क दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आएगी। वन विभाग की जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए मोहदा, सांवलीगढ़, गवासेन सहित अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

प्राकृतिक खेती, मिलेट्स और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के निर्देश

- सामान्य से कम बारिश की आशंका के बीच किसानों को मूंग, उड़द और तिल की खेती की सलाह

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों, आत्मगवर्निंग बोर्ड तथा किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिला कंटीन्जेंसी प्लान के संबंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए कृषि एवं संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में एलनीनो प्रभाव के दृष्टिगत कम वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को कम अवधि वाली फसलें लगाने पर चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि जिले के किसान मूंग, उड़द, तिल एवं अरहर जैसी फसलें ले सकते हैं तथा इन फसलों के बीज जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अधिकारियों ने किसानों को पर्याप्त जल उपलब्धता होने पर ही धान की फसल लेने की सलाह दी।

कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जिले में प्राकृतिक खेती एवं मिलेट्स का रकबा बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान भ्रमण कार्यक्रम के तहत किसानों को बाहरी राज्यों के साथ-साथ जिले के प्रगतिशील किसानों की सफल कृषि पद्धतियों का भी अवलोकन कराया जाए। उन्होंने कृषि, पशुपालन एवं उद्यानिकी विभाग के विभिन्न संसाधनों एवं यंत्रों के लिए एकीकृत केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तावित कृषि योजना के अंतर्गत इंटरक्रॉपिंग, फसल विविधीकरण एवं क्षीर धारा ग्राम योजना सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

वैज्ञानिक पशुपालन बना सफलता की कुंजी, लखपत यादव ने खड़ा किया लाखों का डेयरी व्यवसाय

प्रतिदिन 175 लीटर दूध उत्पादन, मासिक आय पहुंची लगभग 3 लाख रुपये

विदिशा (निप्र)। शमशाबाद विकासखंड के ग्राम वेरखेड़ी घाट निवासी श्री लखपत यादव (पुत्र श्री पूरण सिंह) ने अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता के बल पर पशुपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उनकी कहानी ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है, जो यह साबित करती है कि सीमित संसाधनों से भी बड़े सपने साकार किए जा सकते हैं। मात्र 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले लखपत यादव ने लगभग एक दशक पहले केवल 1-2 भैंसों के साथ पशुपालन की शुरुआत की थी। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन लगभग 30 बीघा कृषि भूमि और मेहनत के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। खेती के साथ-साथ उन्होंने पशुपालन को आय का अतिरिक्त साधन बनाया और धीरे-धीरे इसे अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में विकसित कर लिया।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदान की गई कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं का लाभ उठाकर उन्होंने अपने पशुधन की नस्ल और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार किया। परिणामस्वरूप आज उनके डेयरी फार्म में 25 मुर्रा भैंसें, 23 पड़ियाएं, 5 एचएफ गायें तथा 5 बछियाएं हैं। यह उपलब्धि उनके निरंतर प्रयासों और वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लखपत यादव अपने पशुओं के संतुलित आहार

पर विशेष ध्यान देते हैं। वे चुनी, दलिया, तारा फीड और तिवाना जैसे पोषक आहार के साथ-साथ हरे चारे के रूप में बरसीम और गेहूं की खेती भी करते हैं। बेहतर पोषण और प्रबंधन के कारण उनके फार्म से प्रतिदिन लगभग 175 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है।

उत्पादित दूध को वे विदिशा स्थित सुंदर डेयरी को विक्रय करते हैं, जहां उन्हें औसतन 60 रुपये प्रति लीटर का मूल्य प्राप्त होता है। उनकी मेहनत और सुव्यवस्थित डेयरी प्रबंधन का ही परिणाम है कि आज उनकी मासिक आय लगभग तीन लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ उन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया है। अपने डेयरी व्यवसाय को और अधिक विस्तारित करने के उद्देश्य से उन्होंने कामधेनु योजना तथा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत आवेदन भी किया है। लखपत यादव की सफलता की यह कहानी दर्शाती है कि यदि किसान आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए खेती के साथ पशुपालन को जोड़ें, तो कम संसाधनों से शुरू किया गया कार्य भी बड़े और लाभकारी उद्यम का रूप ले सकता है। उनकी उपलब्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बना जीवनदाता, हाइड्रोसिफेलस से जूझ रहे योगेश को मिला नया जीवन

आयुष्मान योजना के तहत हुआ सफल ऑपरेशन, अब पूरी तरह स्वस्थ है चार माह का बालक

विदिशा (निप्र)। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से चार माह के मासूम योगेश को नई जिंदगी मिली है। जन्मजात हाइड्रोसिफेलस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बालक का सफल ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ जीवन प्रदान किया गया। यह सफलता स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता, समय पर उपचार और योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार के मार्गदर्शन में ग्राम खेजड़ा अहमदपुर,

तहसील एवं जिला विदिशा निवासी श्री कुलदीप कुषवाह के पुत्र योगेश का उपचार चिरायु मेडिकल कॉलेज में

सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। डॉ. कुमार ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान हुई एएनसी जांचों में ही यह संकेत मिल गए थे कि शिशु को जन्मजात हाइड्रोसिफेलस रोग होने की प्रबल संभावना है। परिवार ने प्रसव के दौरान उत्पन्न जटिलताओं के कारण 21 नवंबर 2025 को स्थानीय मेडिकल कॉलेज में बच्चे का जन्म कराया। नवजात के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन चिकित्सकों द्वारा यह जानकारी दिए जाने पर कि बच्चा हाइड्रोसिफेलस रोग से ग्रसित है, परिवार गहरी चिंता में पड़ गया। चिकित्सकों ने स्पष्ट किया कि समय रहते उपचार नहीं कराया गया तो बच्चे के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद परिवार ने बच्चे के उपचार के लिए प्रयास शुरू किए। इसी दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की टीम ने मामले को संज्ञान में लिया और आवश्यक चिकित्सकीय एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर बच्चे का उपचार चिरायु मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित कराया। सभी तैयारियों के बाद 1 अप्रैल 2026 को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की सफलता के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज योगेश पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से विकास कर रहा है। परिवार ने उपचार व्यवस्था एवं सहयोग के लिए स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा आयुष्मान भारत योजना के प्रति आभार व्यक्त किया है। आरबीएसके टीम एवं जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रके स्टाफ द्वारा बच्चे की नियमित फॉलोअप जांच भी की जा रही है, जिससे उसके स्वास्थ्य की सतत निगरानी सुनिश्चित हो सके। यह सफलता कहानी दर्शाती है कि शासन की स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए किस प्रकार जीवनरक्षक साबित हो रही हैं और समय पर पहचान एवं उपचार से गंभीर बीमारियों पर भी प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

राइट क्लिक

श्रीराम मंदिरः 'चढ़ावा चोरी कांड' से उपजे चार नरेटिव !

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी है। इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जो खबरे छनकर आ रही हैं, उससे लगता है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी का बड़ा रैकेट काम कर रहा था और उसे ट्रस्ट के पदाधिकारियों का संरक्षण किसी न किसी रूप में मिला हुआ था। रिपोर्ट में ट्रस्ट में बदलाव तथा जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर की बात भी कही गई है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बदलने की भी बात है। जांच के दौरान ही मंदिर की व्यवस्थाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि खामोशी से ही सही,गड़बड़ी की बात मानी जा रही है। हालांकि जनता के सामने यह रिपोर्ट पूरी जांच के बाद ही आने की संभावना है। इन सबके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई किसी के और खासकर 'बड़े' लोगों के खिलाफ होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी इस बात को लेकर भी संदेह है कि यह एसआईटी, 'स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम' है अथवा 'सेव इनसाइडर्स टीम' है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में किसी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट की भी बात नहीं है। इस मामले में कुछ ठोस कार्रवाई न होने की आशंका के पीछे विश्व हिंदू परिषद एवं अनुषांगिक अन्य संगठनों तथा साधुसंतों द्वारा बनाए जा रहे अलग-अलग नरेटिव हैं, जो एक दूसरे को काटने में भी लगे हुए हैं। जबकि उन राम भक्तों की भावना और नरेटिव पर किसी का ध्यान नहीं है, जो हर हाल में धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में असंदिग्ध पवित्रता और नैतिक ईमानदारी चाहता है। एक मुद्दा 'चढ़ावा चोरी' को 'चंदा चोरी' कहकर 'अंडर एस्टीमेट' करने का भी है। मीडिया का बड़ा वर्ग अब चढ़ावा चोरी को चंदा चोरी कहने लगा है। यह तार्किक रूप से सही नहीं है। क्योंकि चंदा (कंट्रीब्यूशन) तो किटी पार्टी या होली के हुड़दंग के लिए भी दिया जा सकता है। लेकिन चढ़ावा (ऑफरिंग) केवल भगवान को चढ़ता है। यह भक्तिभाव और स्वेच्छा से किया गया दान है। इसे 'चंदा' कहना आस्था का अवमूल्यन करने जैसा है।

बहरहाल, जो सामने आ रहे हैं, यह मीडिया में सुनियोजित तरीके से चलाए जा रहे हैं, वो मुख्य रूप से चार नरेटिव हैं। पहला तो यह कि श्रीराम मंदिर में कहीं कोई रत्तीभर भी घोटाला नहीं हुआ है। वहां काम करने वाले सभी आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं। चढ़ावा चोरी जैसी अपवित्र बातें वो लोग फैला रहे हैं, जो श्रीराम मंदिर और रामजन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टियों को और प्रकारांतर से हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं। मंदिर के हिसाब-किताब में भारी अनियमितता की बातें सामने आने पर ट्रस्ट ने स्वयं एसआईटी बनाने की मांग की। उसी के तहत सारी जांच हो रही है। जिसे कहीं कोई शिकायत हो तो एसआईटी के समक्ष अपनी बात रखे। दोष सिद्ध होने के पहले किसी की नीयत पर शक करना ठीक नहीं। एफआईआर का तो सवाल ही नहीं है। वैसे भी राम भक्तों और मंदिर के बंदों पर एफआईआर कैसी? जहां तक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उनकी कार्यशैली पर उठ रही उंगलियों का सवाल है तो चंपत राय 'महात्मा' हैं। उनके चरित्र पर शक करना भी पाप है। इतने पवित्र वातावरण में भी कहीं कोई छोटी-मोटी त्रुटि हुई होगी तो 'ठीक' कर ली जाएगी। यह बात अलग है कि इस भोले नरेटिव पर बहुत से भाजपा और संघ से जुड़े लोग भी हैरान है।

दूसरा नरेटिव, इस सावधानी के साथ चलाया जा रहा है कि श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी की आड़ में एक वर्ग हिंदू मंदिरों का प्रबंधन फिर से सरकार के हाथों में सौंपना चाहता है। यह कतई नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू मंदिरों का प्रबंधन हिंदू जनता के हाथ में ही रहना चाहिए। जैसे कि अन्य धर्मों के मानने वालों के यहां होता है। यहां तक कि जिन मंदिरों के ट्रस्टों में अभी सरकार का दखल है, वह भी खत्म करके उनका प्रबंधन पूरी तरह हिंदू प्रतिनिधियों के हाथ में दिया जाना चाहिए, फिर उसमें चाहे जितनी गड़बाड़ियां हो। क्योंकि मंदिर प्रबंधन पर हिंदुओं का कब्जा ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाए, उसमें होने वाली हेराफेरी या चोरी चकारी आदि के। इसमें अंतर्निहित सनातन मान्यता यह भी है कि हिंदू केवल इसी बात से अभिभूत रहता है कि मंदिर का मैनेजमेंट हिंदू के हाथ में है। बाकी वह सौ खून भी माफ कर देता है। हिसाब-किताब में गड़बड़ियां तो सांसारिक प्रपंच हैं, मोक्ष प्राप्ति की परम इच्छा रखने वाले हिंदू को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दान, चंदा, चढ़ावे आदि का क्या, इस हाथ से गया, उस हाथ को मिला। किसी का तो भला हुआ। हम तो 'सर्वे भवंतु सुखिनः' के आदि काल से पैरोकार हैं। मंदिर का चढ़ावा अगर किसी के घर की समृद्धि का कारण बन रहा है अथवा किसी दूसरे तरीके से बाजार में ही आ रहा है तो इसमें किसी को ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? ऐसा सोचना सच्चे हिंदू होने का प्रमाण नहीं है। वैसे भी चंदा क्या और चढ़ावा क्या, अंत काल में किसी के साथ नहीं जाने वाला। भगवान सिर्फ भक्ति के भूखे हैं न कि सोने की शिला, चांदी के हार अथवा नकदी के। यूं भी आपकी श्रद्धा भक्ति डायरेक्ट प्रभु तक पहुंच गई, बाकी रह गया माल तो सेवा करने वाले बंदों का भी तो कुछ हक बनता है।

तीसरा नरेटिव, देश में हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए एक सनातन बोर्ड गठित करने का है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग इसे हवा दे रहे हैं। इसके पीछे भाव यह है कि सारे मंदिरों को 'मुस्लिम वक्फ बोर्ड' की तर्ज पर किसी एक बोर्ड के अधीन किया जाए। उसके अपने नियम हों, उसी के तहत मंदिरों को प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार को पहला बोर्ड गठित करना होगा। उसके नियम बनाने होंगे। अगर बोर्ड बने भी तो नियम कायदे सरकार के ही रहेंगे। यह मंदिर प्रबंध स्वतंत्रता समर्थकों को शायद ही मंजूर हो।

चौथा नरेटिव आम राम भक्तों का है, जो केवल और केवल आस्था और श्रद्धा के कारण मंदिरों में जाते हैं। भक्तों को सदा यही आस रहती है कि कभी तो भगवान की कृपा बरसेगी और कभी तो उनके दिन फिरेंगे। मंदिर में चढ़ावा भी वह अपनी श्रद्धा और हैसियत के साथ समर्पित भाव से देता है। अमूमन ज्यादातर भक्त चढ़ावा चढ़ाने के बाद भूल जाते हैं कि उसका कोई हिसाब भी रखना जरूरी है। जो हिसाब होगा, भगवान के घर होगा। बावजूद इस निष्काम भाव के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद राम भक्तों की भावनाओं को ठेस जरूर लगी है और वो आत्मचिंतन के दौर से गुजर रहे हैं। यह भावना बलवती होती जा रही है कि मंदिर में का चढ़ावा भी उसकी खून पसीने की कमाई (दो नंबर की कमाई वालों को छोड़ दें) जिस पर यूं डाका डाला जा रहा है, यह तो सरासर धार्मिक ठगी है। लोग अब तंग हाथ से नकदी चढ़ा रहे हैं।

भारत में मंदिरों के प्रबंधन और चढ़ावे के धन का हिसाब किताब रखने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए तिरूवअंनतपुरम् के पद्मनाभस्वामी मंदिर में दान और वित्तीय प्रबंधन जिला जज की निगरानी में होता है। तिरूपति बालाजी मंदिर में चढ़ावे की गिनती एक बंद लेकिन पारदर्शी कक्ष में होती है, जिसे बाहर से कोई भी देख सकता है। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे और दान की गिनती का हिसाब दिन सार्वजनिक किया जाता है और इस काम में कोई भी भक्त सहभागी हो सकता है। पूरी प्रक्रिया में एडीएम स्तर का अधिकारी और बैंक के अधिकारी मौजूद रहते हैं। शिर्डी के साई बाबा मंदिर का प्रबंधन आदर्श माना जाता है। वहां मंदिर परिसर में रखी दानपेटियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में खोली जाती हैं। गिनती बुलेटप्रूफ कांच वाले सुरक्षित हॉल में होती है। यहां का ऑडिट निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं,बल्कि महाराष्ट्र सरकार का लोकल फंड ऑडिट विभाग करता है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी मंदिर के हिसाब किताब में रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं हुई हो, लेकिन श्रीराम मंदिर प्रबंधन और बाकी मंदिरों के प्रबंधन में अंतर यह है कि वहां गड़बड़ी की जानकारी मिलती ही तुरंत कार्रवाई की गई। उसे बचाने या ढंकने की कोशिश नहीं की गई और न ही इसे मंदिर प्रबंधन कर कब्जे की कोशिशों से जोड़कर देखा गया। लेकिन बदलाव की मांग में भी मंदिर के सुप्रबंधन की बुनियादी अपेक्षा व्यक्ति की नैतिक ईमानदारी, आचरण की पवित्रता और लोक मर्यादा की बात कहीं नहीं की जा रही है, अगर यही सदुण प्रबल हैं तो सारी व्यवस्था की शुचिता स्वतः कायम रहेगी।

अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को

सशक्त उद्यमी-समृद्ध मध्यप्रदेश समिट रवीन्द्र भवन में, मुख्यमंत्री होंगे शामिल

भोपाल (नप्र)। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 पर 'सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्यप्रदेश समिट' शनिवार 27 जून को रविन्द्र भवन, भोपाल में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप और मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन समिट में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

उद्योग आयुक्त श्री दिलीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव भूमि आवंटन, भूमिपूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई, स्टार्टअप एवं स्वरोजगार लाभार्थियों को चेक प्रदान करेंगे। समिट में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं परिधान तथा अभियांत्रिकी क्षेत्रों के एमएसएमई के लिए बायर-सेलर मीट आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई प्रदर्शनी एवं ईज़ ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में लगभग 50 स्टॉल होंगे, जिनमें एमएसएमई, स्टार्टअप, विभागीय स्टॉल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओ.डी.ओ.पी, योजना लाभार्थी, महिला स्व-सहायता समूह, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भोपाल, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल, भारतीय मानक ब्यूरो, लघु राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एन.आई.टी.टी.आर) तथा बैंकों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे, जो प्रतिभागियों को संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करेंगे। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए) भी समिट में भाग लेंगे।

मुख्य सत्र में प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह स्वागत उद्बोधन देंगे। इस दौरान एमएसएमई, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एसआरएलएम (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) तथा आईपीआईपी विभागों की विगत ढाई वर्ष की उपलब्धियों एवं आगामी ढाई वर्ष की कार्ययोजना पर आधारित लघु वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ एमओयू का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिनमें आरएजेडओआरपीएवाय (आरजीपीएक्स प्रा. लि.). प्लग एंड प्ले इंडिया प्रा. लि. तथा बीआईसीसीआई (बैकवर्ड क्लासेज़ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) सम्मिलित है।

3 विषयगत सत्र भी होंगे

समिट में तीन विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रथम सत्र, नये बाजार, नई उडान (एमएसएमई एवं एसएचजी के लिए नए बाजार अवसर) में एफआईईओ, सीएसआई आर-एएमपीआर आई ओएनडीसी, ईसीजीसी एवं इंडिया पोस्ट के पैनलिस्ट भाग लेंगे। दवितीय सत्र पूंजी तक पहुँच (फंडिंग द नेक्स्ट जनरेशन एमएसएमई), में एनपीसीएल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरएक्सआईएल ट्रेन्ड्स प्लेटफॉर्म, आरएजेडओआरपीएवाय एवं नाबार्ड के पैनलिस्ट सम्मिलित हैं। तृतीय सत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड (बीआईएस) के सहयोग से उत्पाद गुणवत्ता पर होगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अप्रैल 2017 में पारित संकल्प के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिवस सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) की प्राप्ति में एमएसएमई की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के आयोजन का दसवां वर्ष है।

...जो एक बार मध्यप्रदेश आता है, वह यहीं का होकर रह जाता है : मुख्यमंत्री डॉ.

राज्य सरकार ने उद्योग अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लागू की हैं पारदर्शी और उद्योग मित्र नीतियां

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समय तभी बदलता है, जब संकल्प बड़ा होता है। सभी भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का समय बदला है। विश्व के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री श्री मोदी को विभूषित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विकसित भारत @2047 और अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का संकल्प लिया है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि इसमें से लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान मध्यप्रदेश का हो। मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवा, सुशासन और जन कल्याण के संकल्पों को पूर्ण करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। वर्तमान में मध्यप्रदेश की गिनती देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में हो रही है। हम विरासत भी और विकास भी के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। उन्होंने रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर किया उनका स्मरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 'विकसित मध्यप्रदेश' विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री श्री चैतन्य काश्यप, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों से राज्य में मौजूद निवेश संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की विशेषता है कि एक बार जो मध्यप्रदेश आता है, यहीं का होकर रह जाता है। कार्यक्रम में उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि, निवेशक, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि तथा नीति निर्माता शामिल हुए।

राज्य सरकार 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को ला चुकी है धरातल पर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ और एमओयू साइन हुए। यह प्रसन्नता का विषय है कि 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को राज्य सरकार धरातल पर ला चुकी है। मध्यप्रदेश की छवि कृषि प्रधान राज्य के साथ उद्योग मित्र राज्य की भी बनी है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार को समर्पित किया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय युवा प्रतिभाओं ने दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों में शीर्ष पदों पर पहुंचकर भारत का मान बढ़ाया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारतीय वैज्ञानिकों ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। राज्य सरकार ने भी अपनी स्पेस-टेक पॉलिसी लॉन्च की है। मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

प्रदेश में पिछले तीन साल से विकास का कारवां लगातार बढ़ रहा है आगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन साल से विकास का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त लैंड बैंक है। राज्य सरकार ने उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करने लिए पारदर्शी और उद्योग मित्र नीतियां लागू की हैं। मध्यप्रदेश की इन्हीं विशेषताओं के कारण निवेशक उद्योग लगाने के लिए राज्य में आ रहे हैं। देश के मध्य में स्थित होने के कारण उन्हें कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स का विशेष लाभ भी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने चारों दिशाओं में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अधोसंरचना विकास पर विशेष बल दिया है।

मध्य प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री

35 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में झमाझम बरसे बादल

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के लिए राहत की बड़ी खबर है। मौसम विभाग के द्वारा 24 जून 2026 की दोपहर को जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा अब प्रदेश के इंदौर और मंडला से होकर गुजर रही है। एमपी में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है, जबकि अगले 24 घंटे में इसके अधिकांश जिलों तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

आईएमडी की चेतावनी, तेज हवा और बिजली का खतरा- आईएमडी ने चेतावनी दी है कि कई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बादलों की तेज गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

भोपाल-इंदौर, खंडवा और बैतूल में तेज बारिश, मानसून 3 से 4 दिन में पूरा प्रदेश कवर करेगा

मध्य प्रदेश में बुधवार (24 जून) को आखिरकार दक्षिण-पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी। सामान्य तिथि से 9 दिन की देरी से पहुंचे मानसून ने बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर समेत कई जिलों में प्रवेश किया, जिसके साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मानसून के पूरे प्रदेश में फैलने का अनुमान जताते हुए 42 जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 घंटे में 39 जिलों में आंधी-बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जून है, लेकिन इस बार लेट हो गया। हालांकि, तीन से चार दिन में पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा।

भोपाल में टैक्सियों का किराया 100 प्रतिशत बढ़ा

एयरपोर्ट से अवधपुरी की प्रीमियम राइड अब 450 रुपए में, सिटी राइड के रेट भी बढ़ेंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल में उबर की एयरपोर्ट राइड पहले से महंगी हो गई है। न्यूनतम किराया 50-60 रुपए से बढ़कर 120-150 रुपए तक पहुंच गया है। करीब 10 साल बाद किराए में यह बढ़ोतरी हुई है। टैक्सी चालक संघ के दबाव के बाद कंपनियों ने सहमति जताई है। ओला और रैपिडो ने भी बढ़ोतरी पर सहमति दे दी है, लेकिन फैसला बाकी है। एयरपोर्ट राइड के न्यूनतम किराए में लगभग 100 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। 220-230 रुपए वाली राइड अब 270-280 रुपए तक पहुंच रही है। 350 रुपए वाली प्रीमियम राइड 440-450 रुपए तक मिल रही है। प्रीमियम कैटेगरी में करीब 25 से 30 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।

ओला ने एयरपोर्ट किराया बढ़ाने पर सहमति जताई- भोपाल टैक्सी चालक संघ के महामंत्री राजेश कुमार नागले ने बताया- उबर ने एयरपोर्ट राइड के किराए में आंशिक सुधार कर दिया है। सिटी राइड के रेट अभी बढ़ना बाकी हैं। ओला और रैपिडो के साथ हुई चर्चा में दोनों ने जल्द किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

भोपाल में कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन, 'फिजिक्स वाला' होगी सील

फायर सेफ्टी और दस्तावेजों में कमी, 40 से ज्यादा सेंटर्स को नोटिस

भोपाल (नप्र)। भोपाल में कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर फायर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में देश के अलग-अलग शहरों में हुई घटनाओं के बाद फायर विभाग ने शहर में व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के नेतृत्व में टीम ने कई कोचिंग संस्थानों की जांच की, जिसमें सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां सामने आई हैं।

40 से अधिक कोचिंग सेंटर्स को नोटिस

निरीक्षण के दौरान फायर विभाग ने करीब 40 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक कई संस्थानों में वेंटिलेशन की कमी, इमरजेंसी एग्जिट की अपर्याप्त व्यवस्था और जरूरी दस्तावेजों का अभाव पाया गया। कुछ जगहों पर बाहर लगे बड़े होर्डिंग्स भी वेंटिलेशन में बाधा बन रहे हैं, जिससे आपात स्थिति में खतरा बढ़ सकता है।

'फिजिक्स वाला' कोचिंग पर कार्रवाई

फायर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिजिक्स वाला नामक कोचिंग क्लास को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इस संस्थान में फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियां और आवश्यक दस्तावेजों का अभाव पाया गया। विभाग ने संकेत दिए हैं कि अन्य संस्थानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।

फायर सिस्टम मिला, लेकिन खामियां बरकरार

निरीक्षण में यह सामने आया कि कई कोचिंग सेंटर्स में फायर सिस्टम लगा हुआ और चालू स्थिति में है। हालांकि इसके बावजूद वेंटिलेशन और सुरक्षित निकासी मार्गों की कमी को गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। फायर विभाग का कहना है कि केवल उपकरण लगाना पर्याप्त नहीं, बल्कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है।

रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई- फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।